घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 237- रविवार 28- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बंगाल में बड़ा राजनीतिक ऐलान....शुभेंदु सरकार लाएगी समान नागरिक संहिता

अवैध घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर भेजने की तैयारी

पश्चिम बंगाल,27 जून 2026। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की राजनीति को गरमाने वाला एक बहुत बड़ा एलान किया है। कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को पूरी तरह लागू करेगी। आम भाषा में समझें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और जमीन-जायदाद से जुड़े नियम-कानून एक समान होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसके साथ ही उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जों, लव जिहाद और जबरन धर्म बदलवाने जैसी गतिविधियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाने की बात कही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संस्कृति का मुद्दा उठाते हुए अवैध घुसपैठियों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत तरीके से सरहद पार करके भारत में आए हैं और देश विरोधी ताकतों की मदद कर रहे हैं, उन्हें बंगाल में किसी भी कीमत पर रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए बॉर्डर से सटे जिलों में होल्डिंग सेंटर यानी अस्थाई निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में पकड़े गए लोगों की पूरी जांच होगी और अवैध पाए जाने पर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी जमीन भी उपलब्ध करा दी है।

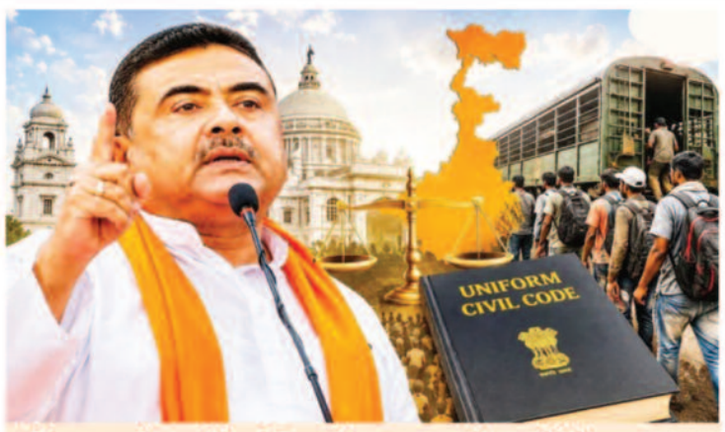

हिंदू शरणार्थी घुसपैठिए नहीं...नागरिकता कानून के तहत मिलेगा पूरा हक

कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच का अंतर भी पूरी तरह साफ किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना यानी धर्म के नाम पर जुल्म सहने के बाद जो हिंदू भारत आए हैं,उन्हें घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को नागरिकता सशोधन कानून यानी सीएए के तहत भारत की पक्की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश की सेना का अपमान करने वालों और आतंकी हमलों पर चुप्पी साधने वाले लोगों को बंगाल की धरती पर मनमानी करने की आजादी बिल्कुल नहीं मिलेगी।

आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का होगा सम्मान

सरकार ने अपने कामकाज के साथ-साथ उन लोगों को याद करने का भी फैसला किया है जिन्होंने देश में लगे आपातकाल का खुलकर विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि आगामी नौ अगस्त को ऐसे सभी संघर्ष करने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी सम्मान पत्र देकर सरकारी तौर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष समिति भी बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर इलाके में एक नए कार्यालय की शुरुआत की। उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि वे हर महीने दो दिन इस दफ्तर में खुद बैठेंगे और आम लोगों से मिलकर उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान करेंगे।

सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी,राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे मुख्यातिथि

पीएम मोदी ने सेशेल्स में कछुओं को पत्तियां खिलाईं

विक्टोरिया (सेशेल्स),27 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर शनिवार को सेशेल्स पहुंचे। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने हवाई अड्डे पर विशेष स्वागत किया। यात्रा के पहले दिन मोदी ने राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया तथा संयुक्त पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। एल्डाब्रा में विशालकाय कछुओं को देखा और भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और घनिष्ठ मित्र है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत बनाने तथा लोगों के हित में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सेशेल्स में अपने स्वागत के दौरान प्रस्तुत कच्छ के पारंपरिक नृत्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जिस प्रकार संरक्षित और जीवंत बनाए रखा है, वह सराहनीय है। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हर्मिनी एक ही वाहन में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पहुंचे। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ सेशेल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में दोनों नेताओं ने संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ मिलकर 'कोको डी मेर' का पौधा लगाया, जो सेशेल्स की विशिष्ट पहचान है और देश के राजचिह्न में भी शामिल है।

सोनोस ने फिर की छंटनी,3 प्रतिशत कर्मचारियों की गई नौकरी

नई दिल्ली,27 जून 2026। प्रीमियम ऑडियो कंपनी सोनोस ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने कुल वर्कफोर्स में करीब 3 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है। यह कदम कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है। सोनोस का कहना है कि संगठन को सरल बनाकर काम की रफ्तार बढ़ाने और नए प्रोडक्ट तेजी से तैयार करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट और डिजाइन टीमों पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई लीडरशिप पद भी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने मार्केटिंग विभाग में भी कई पद खत्म किए थे। सोनोस का कहना है कि अब कम मैनेजमेंट लेयर के साथ टीमें ज्यादा स्वतंत्र होकर काम करेंगी और फैसले भी पहले से तेज गति से लिए जाएंगे। सोनोस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम कॉनराड ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि कंपनी को तेजी से बदलते बाजार के हिसाब से ज्यादा चुस्त बनाना जरूरी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक बैठकों में समय बिताने के बजाय तेजी से फैसले लेने और नए प्रोटोटाइप तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कंपनी का मानना है कि नई संरचना से प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज होगा और ग्राहकों तक बेहतर सेवाएं जल्दी पहुंच सकेंगी। सोनोस पिछले साल अपने नए मोबाइल ऐप को लेकर आलोचना का सामना कर चुकी है। ऐप में कई बग और जरूरी फीचर नहीं होने से ग्राहकों की नाराजगी बढ़ी थी। अब कंपनी नए ऐप अपडेट की टेस्टिंग कर रही है,जिसमें बेहतर नेविगेशन और दूसरे सुधार शामिल हैं। साथ ही,पूरी टेक इंडस्ट्री में एआई पर बढ़ते निवेश और लागत घटाने के लिए कई कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं।

अमेजन,गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई के लिए कर रहीं 5400 अरब रुपये निवेश

नई दिल्ली,27 जून 2026। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निवेश बढ़ा रही हैं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर इस सेक्टर में करीब 57 अरब डॉलर (लगभग 5,400 अरब रुपये) निवेश करने का वादा किया है। हाल ही में अमेजन ने 2030 तक भारत में एआई और क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 13 अरब डॉलर और निवेश का ऐलान किया। इससे कंपनी का कुल निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। अमेजन ने बताया कि नया निवेश मुंबई और हैदराबाद में एडब्ल्यूएस डाटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने पर खर्च होगा। इससे स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को एआई चिप्स, क्लाउड सेवाएं और डेवलपर टूल्स आसानी से मिल सकेंगे। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2029 तक भारत में 17.5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की थी। वहीं गूगल भी विशाखापत्तनम में बड़ा एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर निवेश कर रहा है और कई नई सुविधाएं विकसित करेगा। कंपनियों का मानना है कि भारत में मजबूत इंजीनियरिंग प्रतिभा, तेजी से बढ़ती डिजिटल पहुंच और एआई अपनाने की रफ्तार इसे बड़ा बाजार बना रही है। अमेजन के सीईओ एंडी जेस्सी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि भारत भविष्य में एआई विकास का अहम केंद्र बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लगातार विस्तार करने की तैयारी कर रहा है और नई तकनीकों पर लगातार काम करेगा।

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार दोनों गार्ड की जमानत पर भी पटना कोर्ट में 30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना,27 जून 2026। बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई अपडेटेड केस डायरी की जांच के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए खान सर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा राहत को जारी रखने का आदेश दिया है। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में ताजा केस डायरी पेश की,जिसकी जांच के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। खान सर की ओर से पेश वकील अरविंद कुमार मौर ने सरकारी वकील के अतिरिक्त समय मांगने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केस डायरी पहले ही उपलब्ध थी और बहस पूरी की जा सकती थी। लेकिन कोर्ट ने सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

महाराष्ट्र के ठाणे में परीक्षा से पहले लीक हुआ टीईटी का पेपर,स्थगित हुई परीक्षा

ठाणे,27 जून 2026। महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमएएचए टीईटी 2026) का पेपर एक दिन पहले ठाणे के भिवंडी में लीक हो गया। ऐसे में सरकार ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस और शिक्षा विभाग को जानकारी मिली थी कि भिवंडी इलाके में किसी के पास टीईटी का प्रश्न पत्र मौजूद है। मामले की गहन जांच के बाद एफआईआर दर्ज करते हुए अब आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने 28 जून को आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। परिषद की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। शनिवार सुबह गोपनीय सूचना पर भिवंडी में पुलिस ने छापेमारी की। इसमें अधिकारियों को कुछ प्रश्न टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। परिषद ने कहा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे मामले की जांच पूरी होने तक रविवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया है। अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी परिषद की वेबसाइट से ही प्राप्त करें। नई परीक्षा तारीख की घोषणा जांच पूरी होने के बाद की जाएगी। शिक्षा विभाग यह सत्यापन कर रहा है कि बरामद पेपर आज होने वाले टीईटी परीक्षा का असली पेपर है या कोई गैस पेपर है। अगर दोनों पेपर मेल खाएंगे तो ऐसे में पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश के साथ शिक्षा विभाग शुरू होने वाली अन्य परीक्षाओं को रद्द करने पर भी विचार कर सकता है। इस विषय में अभी तक पुलिस और शिक्षा विभाग किसी की भी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पेपर लीक अब कोई अपवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह इस दरिद्र सरकार की पहचान बन गया है। कल महाराष्ट्र में होने वाली टीईटी परीक्षा का पेपर उपमुख्यमंत्री शिंदे के ठाणे में ही लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत, सपनों और भविष्य पर पानी फेरने वाले रैकेट को किसका राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है? एमएएचए टीईटी 2026 में पेपर-1 और पेपर-2 शामिल हैं।

खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत : FSSAI ने बदले नियम,अब रिकॉर्ड रखने की झंझट से मिलेगी छूट

नई दिल्ली,27 जून 2026। केंद्र सरकार ने खाद्य कारोबार से जुड़े व्यवसायों को बड़ी राहत देते हुए FSSAI के नियमों में अहम बदलाव किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मकसद 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और अनावश्यक नियामकीय बोझ कम करना है।

गैर-विनिर्माण कारोबारियों को मिली छूट

नए नियमों के तहत अब गैर-विनिर्माण खाद्य कारोबारियों को कुछ रिकॉर्ड रखने और स्टॉक रोटेशन से जुड़े नियमों का पालन करने से छूट मिलेगी। पहले सभी लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट के आधार पर स्टॉक का प्रबंधन और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था। अब यह व्यवस्था केवल खाद्य निर्माण इकाइयों पर ही लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे खुदरा विक्रेताओं और अन्य गैर-विनिर्माण खाद्य व्यवसायों, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ काफी कम होगा।

खाद्य निर्माताओं पर पहले जैसे नियम

हालांकि, खाद्य निर्माण करने वाले कारोबारियों के लिए ये नियम पहले की तरह लागू रहेंगे, ताकि खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और उत्पाद की ट्रेसबिलिटी से कोई समझौता न हो। जहां निगरानी जरूरी है, वहां नियंत्रण पहले की तरह मजबूत बना रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला खाद्य क्षेत्र में जोखिम आधारित और परिणाम केंद्रित नियामकीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई नियम आसान किए हैं।

बद्री-केदार मंदिर समिति पर भ्रष्टाचार का आरोप,आरटीआई खुलासे से मचा बड़ा बवाल

नई दिल्ली,27 जून 2026। अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़े विवादों के बाद अब उत्तराखंड की बद्री-केदार मंदिर समिति भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बड़ा खुलासा किया है। नेगी का आरोप है कि मंदिर समिति के कई सदस्यों ने एक साल से कम समय में ही यात्रा एवं दैनिक भत्ते के नाम पर लाखों रुपये का अनियमित भुगतान लिया है। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए दान के धन का खुला दुरुपयोग करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान नेगी ने स्पष्ट किया कि मंदिर एक्ट की धारा 26(च) के अनुसार, समिति के सदस्यों को केवल आधिकारिक बैठकों या समिति से संबंधित कार्यों के लिए ही भत्ते दिए जा सकते हैं। नियमानुसार, सदस्यों को विधायकों के बराबर प्रतिदिन 6,000 रुपये का दैनिक भत्ता और 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय देय है। नेगी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष जून में मनोनीत हुए इन सदस्यों ने मात्र आठ महीनों में ही संदिग्ध तरीके से भारी धनराशि निकाल ली, जबकि इस दौरान बोर्ड की आधिकारिक बैठक केवल एक बार हुई थी।

केतन हत्याकांड में नए खुलासे...डिलीट चैट्स और साहिल के बयान से बढ़ी जांच

पुणे,27 जून 2026। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से पुलिस ने करीब 10 घंटे तक गहन पूछताछ की। साहिल ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सिया ने केतन के प्रति अपनी अनिच्छा या किसी परेशानी के बारे में परिवार को पहले बताया होता,तो उनका परिवार निश्चित रूप से यह शादी रद्द कर देता। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या साहिल को अपनी बहन और चेतन चौधरी के बीच के अवैध संबंधों की जानकारी पहले से थी और यदि थी, तो उन्होंने इसे परिवार से क्यों छिपाया। केतन हत्याकांड की जांच कर रही टीम के अनुसार, आरोपी सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद की सभी महत्वपूर्ण चैट्स को अपने फोन से हटा दिया था। उन्होंने मोबाइल का रिसाइकल बिन भी पूरी तरह साफ कर दिया था ताकि पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत न लगे। जांच में सामने आया है कि 18 जून की घटना के बाद दोनों ने डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। अब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा है ताकि डिलीट किए गए डेटा और चैट लॉग्स को रिकवर किया जा सके और इस खौफनाक साजिश की पूरी परतें खुल सकें। आरोपी सिया ने पुलिस के सामने एक नया और चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा है कि केतन सिर पर विग लगाता था, जो उसे पसंद नहीं था, और इसी वजह से वह शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं,केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केतन के सिर पर मामूली मेडिकल कारणों से बालों का एक छोटा पैच कम था,जिसकी जानकारी सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को दी गई थी। पिता के अनुसार,यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं था और सिया के पास शादी से इनकार करने के कई अवसर थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सिया और चेतन की मुलाकात कैसे हुई।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आस्था से खिलवाड़...प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल

राम मंदिर दान की कथित चोरी दुखद और शर्मनाक,पारदर्शी जांच हो : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली,27 जून 2026। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर में दान और चंदे के गबन के मामले को अत्यंत दुःखद और शर्मनाक करार दिया है। वायनाड (केरल) में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इस घटना को देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धापूर्वक अपना योगदान दिया था,आज उनका भरोसा टूटा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि मंदिर निर्माण के नाम पर फंड जुटाया गया था, तो उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन्होंने इस मामले में स्पष्ट जवाबदेही तय करने की पुरजोर मांग की है।

जनता की मेहनत की कमाई का हिसाब कौन देगा? प्रियंका गांधी ने इस मामले के भावनात्मक पहलू पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा दिया गया चंदा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि देश की महिलाओं ने अपनी छोटी-छोटी बचत से और गरीबों ने अपनी मेहनत की कमाई से यह दान दिया है। जब आम नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई मंदिर के लिए अर्पित करता है, तो उसे सुरक्षित रखना और उसका पारदर्शी प्रबंधन करना आयोजकों की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने कहा कि चंदा अभियान के दौरान जिस तरह से लोगों को प्रेरित किया गया था, अब उसी गंभीरता के साथ उन लोगों को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह सब कैसे और क्यों हुआ।

एसआईटी की कार्रवाई : अब तक क्या हुआ? राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का यह विवाद 7 जून को प्रकाश में आया था। इस गंभीर मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एक विशेष जांच दल का गठन किया। एसआईटी ने मामले की प्रारंभिक जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को आधार बनाकर 25 जून की रात को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कार्रवाई करते हुए अयोध्या पुलिस ने शुक्रवार तक मामले में आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, ये सभी आरोपी 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं।

संपादकीय

हर ज्ञान की एक उम्र होती है...

हाल में इटली से खबर आई कि वहां स्कूलों में यौन शिक्षा देने के लिए पहले माता-पिता और अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। वहां के वामपंथियों और ग्रीन पार्टी वालों ने इसका विरोध किया। कहा कि यह आदेश तो ऐसा है जैसे इटैलियन भाषा सिखाने से पहले माता-पिता से पूछा जाए। इटली यूरोप का देश है। वहां ऐसा आखिर क्यों हो रहा है?

अब तक यौन शिक्षा देने की वजह यह बताई जाती रही है कि इससे बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आती है। बच्चे अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, लेकिन यदि पश्चिमी देशों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगे,तो इसका अर्थ यही माना जाना चाहिए कि वहां जनता का एक बड़ा तबका ऐसा नहीं चाहता।

इसका एक कारण यह भी है कि वहां बच्चे बहुत कम उम्र से ही यौन क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। बहुत से बच्चे खेलने और पढ़ने की उम्र में माता-पिता बन जाते हैं। कई बार तो मात्र 10-12 वर्ष की उम्र में ही। वहां टीन एज प्रेगनेंसी भी बहुत है।

कुछ समय पहले ब्रिटेन की एक खबर यह थी कि वहां एक 14 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में उस लड़की ने कहा कि उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसने गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया था। उसका मासिक धर्म भी नियमित था। ऐसी ही एक और खबर थी कि 12 वर्ष का एक बच्चा पिता बन गया।

इस बच्चे के संपर्क में आने वाली लड़की की उम्र 15 साल थी। ऐसा तब हुआ, जब ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देशों में स्कूलों में बचपन से ही यौन शिक्षा दी जाती है और स्कूलों में गर्भ निरोधक गोलियों की मशीनें भी लगी रहती हैं। पश्चिमी देशों में रहने वाले बहुत से भारतीय माता-पिता इससे परेशान हैं। अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला,जिनकी दो बच्चियां हैं,का कहना है कि वे उन्हें यहां नहीं पालना चाहतीं।

वे भारत वापस आना चाहती हैं,क्योंकि वहां के डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्ची के नौ वर्ष के हो जाने के बाद उसे नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियां दी जाएं,जिससे वह अनचाहे गर्भ से बच सके। यह स्थिति डरावनी भी है। क्या वाकई स्कूलों में यौन शिक्षा देने से बच्चों को कोई सीख मिलती है?

2024 में पहली बार यूनिसेफ ने दुनियाभर में होने वाले यौन अपराधों का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि दुनिया में आठ में से एक बच्ची या किशोरी के साथ यौन अपराध होता है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, 11 में से एक लड़का भी इसका शिकार बनता है। एक अन्य रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिका में हर नौ मिनट में एक बच्चा ऐसे अपराधों का शिकार होता है। वहां की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 63 हजार बच्चे ऐसे अपराधों का शिकार बनते हैं...नौ में से एक लड़की और 20 में से एक लड़का। इनमें से 82 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष से कम उम्र की होती हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए,तो एप्सटीन फाइल्स तो एक उदाहरण मात्र है। चाइल्ड राइटस संस्था ने अपने सर्वेक्षण में यह पाया कि पश्चिमी यूरोप के देशों में लगभग पचास लाख बच्चे दुष्कर्म और अन्य यौन अपराधों के शिकार हैं। लड़कियों में यह संख्या 9.7 प्रतिशत और लड़कों में 3.9 प्रतिशत है। 19 यूरोपियन देशों के अध्ययन में पता चला कि 5.3 प्रतिशत लड़कियां और 1.6 प्रतिशत लड़के दुष्कर्म जैसे अपराध झेलते हैं।

अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश ऐसे हैं,जिनके यहां स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाती है। मगर इस कारण यौन अपराध रुक गए हों, ऐसा नहीं है। वहां बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि बच्चों का यौन गतिविधियों में लिप्त होना उनका अधिकार है। भारत समेत तमाम एशियाई देशों की इस बारे में आलोचना की जाती है कि इन देशों में बच्चों को माता-पिता और अभिभावक अपने दवाब में रखते हैं। वे उन्हें यौन आजादी नहीं देते। यौन शिक्षा का भी अभाव है। फिर एक ही झटके में भारत जैसे तमाम देशों को वैचारिक रूप से पिछड़ा साबित कर दिया जाता है।

हमारे यहां भी इन बातों से प्रेरणा लेकर बहुत से लोग स्कूलों में यौन शिक्षा देने की वकालत करते नजर आते हैं। यदि वाकई इससे बच्चों के प्रति ये भयंकर अपराध रुक सकते हों,तो पश्चिमी देशों में आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? यदि बारह-चौदह साल की उम्र में माता-पिता बनना ठीक है,तो उन तर्कों का क्या हो,जो कहते हैं कि कम उम्र में मां बनना लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई लड़की बचपन में ही मां बन जाएगी,तो वह पढ़ेगी-लिखेगी क्या? इस बच्ची के बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी उसके माता-पिता की होगी। एक तरह से दोहरा भार।

जब से इटली की खबर पढ़ी है,तब से यही लग रहा है कि एक तरफ तो वहां परिवार का ही निषेध किया जाता है,तो दूसरी तरफ बच्चे मां-बाप बन जाते हैं। इसीलिए वे लोग भी चाहते हैं कि बच्चे पहले पढ़ें, लिखें, फिर जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल हों। वे ये भी जानते हैं कि यौन शिक्षा से अपराध भी कम नहीं होते। इसीलिए यह बात सही मालूम पड़ती है कि हर संस्कृति की अपनी एक समझ होती है। हर ज्ञान की एक उम्र होती है।

बचपन से ही बड़ों के जीवन का ज्ञान देने लगेंगे,तो कई बार वह औंधे मुंह गिरेगा। इसके अतिरिक्त जिन कारणों के निवारण के लिए उसे दिया गया,उसका भी निदान नहीं हो सका।

वेनेजुएला का भूकंप : मानवीय त्रासदी और आपदा-तैयारी की वैश्विक चेतावनी

काँपी धरती,टूटी जिंदगियाँ

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है,तब वह मनुष्य की तकनीकी उपलब्धियों,आर्थिक प्रगति और प्रशासनिक दावों की वास्तविक परीक्षा लेती है। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ ही क्षणों में वर्षों की मेहनत,सपने और सुरक्षित जीवन का भ्रम मलबे में बदल सकता है। धरती के कुछ सेकंड के कंपन ने न केवल इमारतों को गिराया,बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदों,आजीविकाओं और भविष्य को भी गहरे संकट में डाल दिया।

भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ केवल भूगर्भीय घटनाएँ नहीं होतीं;वे किसी राष्ट्र की तैयारी,शासन-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और मानवीय संवेदनशीलता की भी परीक्षा होती हैं। मलबे में दबे लोगों की पुकार,अपने परिजनों को खोजते परिवार,अस्पतालों में उपचार की प्रतीक्षा करते घायल, राहत शिविरों में अस्थायी जीवन और भय के साये में बीतती रातें यह बताती हैं कि आपदा का वास्तविक दर्द आँकड़ों से कहीं अधिक गहरा होता है।

वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक चुनौतियों,संसाधनों की कमी और प्रशासनिक दबावों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में आई यह प्राकृतिक आपदा केवल भौतिक विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था,परिवहन,बिजली, पेयजल और राहत प्रणाली पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है। यही कारण है कि किसी भी आपदा का प्रभाव उस समाज में अधिक व्यापक होता है,जहाँ बुनियादी ढाँचा पहले से ही कमजोर हो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आपदाएँ सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित नहीं करतीं। सुरक्षित और मजबूत भवनों में रहने वाले लोग अपेक्षाकृत कम नुकसान झेलते हैं,जबकि कमजोर निर्माण,अनियोजित बस्तियाँ और सीमित संसाधनों वाले परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। गरीब,श्रमिक, महिलाएँ,बच्चे,बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिक आपदा की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। इसलिए प्राकृतिक आपदा धीरे-धीरे सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी चेहरा बन जाती है।

यहीं से शहरी नियोजन का महत्व सामने आता है। यदि शहरों का विकास वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो, भवनों का निर्माण भूकंपरोधी तकनीकों से किया जाए, खुले सुरक्षित स्थान उपलब्ध हों,आपात कालीन निकासी मार्ग विकसित किए जाएँ और अस्पतालों को आपदा-तैयार बनाया जाए,तो जान-माल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दुर्भाग्य से अनेक देशों में भवन निर्माण नियमों की अनदेखी, अवैध निर्माण और कमजोर निगरानी ऐसी त्रासदियों को और भयावह बना देते हैं।

भूकंप के बाद के शुरुआती 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही वह समय होता है जब मलबे में दबे लोगों को जीवित निकालने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसलिए राहत एवं बचाव कार्यों की गति, समन्वय और दक्षता ही अनेक लोगों के जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। बचाव दल, चिकित्सक,अग्निशमन कर्मी,सेना,स्थानीय प्रशासन और

स्वयंसेवी संगठन इस कठिन समय में आशा की सबसे बड़ी किरण बनते हैं। राहत कार्य केवल भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने तक सीमित नहीं होते। अस्थायी आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की सुरक्षा,महिलाओं की आवश्यकताओं तथा संचार सेवाओं की बहाली भी समान रूप से आवश्यक होती है। किसी भी आपदा का वास्तविक पुनर्वास तभी संभव होता है जब प्रभावित लोगों को केवल जीवित रहने का सहारा ही नहीं,बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन फिर से शुरू करने का अवसर भी मिले।

ऐसी त्रासदियाँ शासन की विश्वसनीयता की भी परीक्षा लेती हैं। जनता यह देखती है कि संकट की घड़ी में सरकार कितनी शीघ्र,पारदर्शी और प्रभावी ढंग से कार्य करती है। स्पष्ट सूचना, त्वरित निर्णय,संसाधनों का समुचित वितरण और प्रशासनिक समन्वय लोगों का विश्वास बनाए रखते हैं। इसके विपरीत, यदि शुरुआती घंटों में भ्रम, विलंब या सूचना का अभाव हो, तो संकट और अधिक गहरा जाता है। आज आपदा-प्रबंधन केवल राहत कार्यों तक सीमित अवधारणा नहीं रह गया है। आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि आपदा आने से पहले तैयारी सबसे बड़ा बचाव है। विद्यालयों, कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में नियमित मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण,स्थानीय स्वयंसेवी नेटवर्क,समय पर चेतावनी प्रणाली और जन-जागरूकता कार्यक्रम हजारों लोगों का जीवन बचा सकते हैं। नागरिकों को यह जानकारी होना कि भूकंप के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है,किसी भी तकनीकी व्यवस्था जितना ही महत्वपूर्ण है।

इस त्रासदी का एक वैश्विक पक्ष भी है। प्राकृतिक आपदाएँ राष्ट्रीय सीमाएँ नहीं देखतीं। जब किसी देश की क्षमता सीमित पड़ जाती है,तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग मानवता का सबसे मजबूत आधार बनता है। राहत सामग्री, चिकित्सा दल, खोज एवं बचाव विशेषज्ञ,तकनीकी सहायता,अस्थायी आश्रय और पुनर्निर्माण सहयोग जैसे प्रयास वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करते हैं। यह वह समय होता है जब राजनीति से अधिक मानवता की आवश्यकता होती है।

जलवायु परिवर्तन और तीव्र शहरीकरण के इस दौर में दुनिया के अधिकांश देश किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के जोखिम का सामना कर रहे हैं। भूकंप को रोका नहीं जा सकता,लेकिन उसके विनाशकारी प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, मजबूत अधोसंरचना, कठोर भवन मानक,सतत शहरी नियोजन और प्रभावी आपदा-प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है।

वेनेजुएला की यह त्रासदी विश्व समुदाय के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित समाज केवल आर्थिक विकास से नहीं बनते,बल्कि दूरदर्शी नीतियों, मजबूत संस्थाओं,वैज्ञानिक सोच और नागरिक सहभागिता से निर्मित होते हैं। विकास तभी सार्थक है जब वह संकट की घड़ी में लोगों के जीवन की रक्षा कर सके।

अंततः, किसी भी भूकंप की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विज्ञान, उसका संगठन और उसकी संवेदना है। राहत,पुनर्वास, सुरक्षित निर्माण,आपदा-तैयारी और सामाजिक एकजुटता—ये पाँच स्तंभ भविष्य की त्रासदियों को कम करने की दिशा में सबसे प्रभावी उपाय हैं।

वेनेजुएला की पीड़ा केवल एक देश की पीड़ा नहीं है; यह पूरी मानवता के लिए चेतावनी है कि आपदाएँ अचानक आती हैं, लेकिन उनसे होने वाली क्षति हमारी तैयारी तय करती है। इसलिए आवश्यक है कि हम हर त्रासदी को केवल समाचार बनाकर न छोड़ दें, बल्कि उसे भविष्य को सुरक्षित बनाने की प्रेरणा में बदलें। यही इस दुखद घटना के प्रति सच्ची संवेदना और सबसे सार्थक श्रद्धांजलि होगी।

एक अफसाना...

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़

पहाड़ों की ओट से जब सूरज की पहली किरन निकलती, तो वादी-ए-चिनार सुर्ख़ सुनहरी रोशनी में नहा जाती। इसी वादी के दामन में एक छोटा सा पहाड़ी गाँव आबाद था, और इस गाँव के मज़ाफ़ात (बाहरी हिस्से) में बंजारों ने अपने डेरे डाल रखे थे। रेशमाँ भी उन्हीं बंजारों की एक अल्हड़, आज़ाद पंछी जैसी लड़की थी। उसकी आँखों में पहाड़ी झरनों की चमक और हँसी में वादियों की गूँज थी। वह जितनी मासूम थी, उतनी ही ख़ुद्दार भी। लेकिन इस मासूमियत पर गाँव के ताकतवर, जालिम और मगरूर मुखिया के इकलौते बेटे जागीर की काली नज़र थी। जागीर न सिर्फ घमंडी था, बल्कि रेशमा की खूबसूरती को देखकर उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को आमादा था। वह जबरदस्ती रेशमा से शादी करना चाहता था।

रेशमाँ का काम रोज़ जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनना और पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ इकट्ठी करना था। लेकिन अब उसका यह रास्ता महफ़ूज़ नहीं रहा था। जागीर अक्सर अपने हथियाबंद गुंडों के साथ उसका रास्ता रोकता। कभी वह घोड़े पर सवार होकर रेशमा के करीब से इस तरह गुज़रता कि धूल का गुबार उड़ जाता, तो कभी उसके बंजारन वाले पहनावे और पाज़ेब की छनक पर फब्तियां कसता। ऐ बंजारन! ये पैरों की छनक संभाल कर रख, बहुत जल्द ये मेरे महल की दासी बनने वाली हैं,जागीर अपनी मूंछों पर ताव देकर हंसता। रेशमा को उसकी यह बदतमीजी और छेड़छाड़ सख्त नापसंद थी। वह अपनी खुद्दारी से उसे झिड़क देती,जिससे जागीर की सनक और बढ़ जाती। मुखिया ने बंजारों को अपनी ज़मीन पर डेरे डालने की इजाज़त भी इसी गुप्त शर्त पर दी थी कि जवान होने पर रेशमाँ उनके घर की बहू—या यूँ कहें कि जागीर की बंधक बनेगी। रेशमा के गरीब कबीले वाले मुखिया के डर से खून का घूंट पीकर रह जाते थे। एक रोज़, जब रेशमाँ जागीर के खौफ़ से दूर एक गहरे, एकांत चश्मे (झरने) के पास बैठी अपनी चाँदी की पाज़ेब पानी से साफ़ कर रही थी, तो पानी में एक अक्स उभरा। उसने चौंककर ऊपर देखा। सामने एक ऊँची चट्टान पर एक कड़ियल जवान खड़ा था।

वह संगलाख़ (पथरीली) चोटियों के बागी कबीले का लड़का, ज़मान था। ज़मान की आँखों में एक अजीब सा ठहराव और चेहरे पर पहाड़ों का जलाल था। पहली नज़र का वह टकराव दोनों के दिलों में एक ऐसी आग लगा गया जो फिर कभी न बुझ सकी। फिर यह रोज़ का मामूल बन गया। कभी चिनार के साए तले, तो कभी बहते झरने के किनारे, दोनों चोरी-छिपे मिलने लगे।

दहेज : शादी या सौदा?

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,बिहार

दहेज एक ऐसा शब्द है जिस कारण भ्रूण हत्या होता है। लोग दहेज के डर से अपनी बच्चियों को कोख में ही मार देते हैं तो कुछ बेटियों को इसी दहेज के कारण आत्महत्या करना पड़ता है तो कुछ हँसती-खेलती लड़कियों को ससुराल वालों के हाथों ही मार दिया जाता है। शादी के वक्त बेटी को खुशी से दिया जाने वाला तोहफ़ा,अब सौदा सा लगता है। शादी तय करते समय ही लड़की से ज़्यादा उससे मिलने वाले सामान का हिसाब लगाया जाता है। खुद के बेटे का कीमत लगाया जाता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है तो मुझे इतना पैसा व सामान चाहिए और सबसे शर्मनाक बात - इस समाज की, इस शादी के सौदे की जिसमें लड़की वाले पैसे के साथ-साथ खुद की बेटी को भी देते है लेकिन लड़के वालों का पेट भरता ही नहीं वो बेशर्म जैसे माँगते रहते हैं वो भी बिना सोचे समझे। आज -कल बेटी पैदा होते ही माँ-बाप की नींद उड़ जाती है। परवरिश की चिंता बाद में,पहले दहेज जोड़ने की टेंशन शुरू हो जाती है। बेटी के शादी के नाम पर पैसा जमा करने लगते हैं,सोना खरीदने लगते हैं,शादी में बाइक व गाड़ी देने के लिए पैसे जोड़ने लगते हैं मानो बेटी पैदा नहीं हुई,कोई लोन ले लिया हो जिसे ब्याज समेत चुकाना है। इस समाज में सबसे खराब और सबसे दर्दनाक मंजर शादी के बाद शुरू होता

है। जब लड़की को ये सुनने को मिलता है कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है? पड़ोस में देख कार दिया है। तुझे तो फ्री में लेकर तेरी जिंदगी बना दिए ऐसी ऐसी शब्दों को हर रोज सुनना पड़ता है साथ ही ताने,गालियाँ,मारपीट सब सहना पड़ता है और जो इस दुख - दर्द को सह नहीं पाती है वो एक दिन अखबार की हेडलाइन बन जाती है लेकिन फिर भी ये समाज बदलता नहीं क्योंकि उनके घर में थोड़ी हुआ है। आज - कल मानो लड़की इंसान है ही नहीं,वो तो दहेज लाने वाली मशीन बन गई है । मशीन खराब निकली तो जान से मार दो। ये समाज सिर्फ लड़की को समझाता कि एडजस्ट कर लो, शादी में होता ही है ये सब लेकिन कोई लड़कें को क्यों नहीं समझाता। भले 21वीं सदी में मंगल पर यान भेजे जा रहे हैं,पर दिमाग अभी भी दहेज के दलदल में धंसा है।दहेज को इनकार करो। लालच को इनकार करो।क्योंकि शादी दो परिवारों का मिलन है, दो व्यापारियों का सौदा नहीं।

वन्यजीव नहीं,उजड़ते जंगल गांवों के दरवाज़े पर हैं...

गांवों पर बढ़ता वन्यजीव संकट, विकास नीति पर उठते सवाल सिकुड़ते जंगल,बढ़ता भय-विकास की कीमत कौन चुकाएगा?

प्रो.आर.के.जैन
अरिजीत बड़वानी,
मध्यप्रदेश

जंगलों से उठती आह अब गांवों की दहलीज तक सुनाई देने लगी है। आधी रात खेतों में उतर ते हाथी,बस्तियों के आसपास मंडराते तेंदुए और घरों की चौखट तक पहुंचते बाघ केवल वन्यजीव नहीं,बल्कि उस अंधाधुंध विकास के मौन साक्ष्य हैं जिसने उनसे उनका आशियाना छीन लिया। विडंबना यह है कि जिस देश ने सदियों तक वृक्षों को देवता और वन्यजीवों को प्रकृति का परिवार माना,वहीं आज गांवों में जंगल का नाम भय का पर्याय बनता जा रहा है। यह संघर्ष किसी एक किसान और एक जानवर के बीच नहीं,बल्कि उस बिगड़े संतुलन की कहानी है जिसमें मनुष्य ने प्रकृति की सीमाएं लांघ दीं और अब प्रकृति उसी भाषा में जवाब दे रही है। सवाल यह नहीं कि वन्यजीव गांवों में क्यों आ रहे हैं,असली सवाल यह है कि उनके जंगल आखिर बचे कहां हैं?

आंकड़े बताते हैं कि यह संकट अब भयावह हकीकत बन चुका है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच हाथियों के हमलों में 2700 से अधिक लोगों की जान गई,यानी हर साल करीब पांच सौ परिवार उजड़ रहे हैं। बाघों और तेंदुओं के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खेतों की तबाही ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। महाराष्ट्र में वन्यजीवों से कृषि नुकसान प्रतिवर्ष दस हजार से चालीस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के कोडागु में आधे किसान हर साल करीब नब्बे हजार रुपये गंवा रहे हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक किसान वन्यजीवों को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं,क्योंकि उनकी आधे से अधिक फसल जंगल निगल जाता है। जलवायु परिवर्तन, सिकुड़ते जंगल और बेलगाम विकास ने ऐसी स्थिति बना दी है कि न जंगल सुरक्षित हैं,न गांव।

मध्यप्रदेश का बावनगजा भी इस बढ़ते संकट की आहट महसूस कर रहा है। दुनिया यहां 52 गज ऊंची जैन प्रतिमा देखने आती है, लेकिन स्थानीय लोग वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही का असर भी देख रहे हैं। भीषण गर्मी से जंगलों के जलस्रोत सूख गए,भोजन घटा और वन्यजीव गांवों की ओर उतर आए। दिन में श्रद्धालुओं की घंटियां गूंजती हैं,रात में जंगल की हलचल बढ़ जाती है। कई बार खेतों को नुकसान पहुंचता है और ग्रामीणों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। बावनगजा आज केवल तीर्थ नहीं,बल्कि उस राष्ट्रीय संकट का प्रतीक बन चुका है,जहां प्रकृति और विकास आमने-सामने खड़े हैं।

यह संकट अब खेतों से निकलकर पूरे ग्रामीण जीवन पर छा चुका है। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते बदलते हैं। महिलाएं जंगल की ओर कदम बढ़ाने से पहले कई बार सोचती हैं। बुजुर्ग रातभर घर और खेत की रखवाली करते हैं। भय अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। उधर मुआवजे की जटिल प्रक्रिया पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ा देती है। सरकारी फाइलें उस किसान का दर्द नहीं समझती,जिसकी फसल,मवेशी या अपना एक पल में छिन गया। नतीजा यह है कि जिस समाज ने कभी वन्यजीवों को पूजनीय माना था,वही आज उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा है। सह-अस्तित्व की भारतीय परंपरा अब अविश्वास में बदलती जा रही है।

इस संकट का हल केवल बंदूक, पिंजरे या वन्यजीवों को खदेड़ने में नहीं है। रास्ता वहीं निकलेगा,जहां विज्ञान, संवेदना और प्रभावी नीति साथ चलें। जंगलों के प्राकृतिक कॉरिडोर सुरक्षित हों, सौर फेंसिंग और सुरक्षा खाइयां बनें, रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली विकसित हो तथा गांवों तक त्वरित चेतावनी पहुंचे। सबसे जरूरी है कि नुकसान का मुआवजा पारदर्शी और समयबद्ध मिले, ताकि किसान को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि विकास परियोजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं,तो जंगलों की सीमा पर देश की पहली चौकी बने लोगों की सुरक्षा और सम्मान भी उतनी ही प्राथमिकता का विषय होना चाहिए।

बावनगजा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती। सामुदायिक गश्त,वन विभाग और ग्रामीणों के बीच सतत संवाद,वैज्ञानिक इको-टूरिज्म तथा हर्बल खेती, वन-उत्पाद आधारित उद्योग और पर्यटन से जुड़ी आजीविकाएं इस संकट को अवसर में बदल सकती हैं। जब गांव की आजीविका जंगल से जुड़ेगी,तब जंगल दुश्मन नहीं,सहयोगी बनेगा। बच्चों की शिक्षा में भी वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व को केवल पाठ्यक्रम नहीं,बल्कि जीवन-दृष्टि बनाना होगा। आखिर संरक्षण कानूनों से नहीं,संस्कारों से मजबूत होता है।

सबसे बड़ा सवाल हमारी विकास नीति के सामने खड़ा है। क्या विकास का अर्थ केवल जंगल काटकर सड़कें बिछाना है? क्या प्रगति का पैमाना सिर्फ कंक्रीट का विस्तार है? यदि यही सोच रही, तो आने वाले वर्षों में गांवों और जंगलों का संघर्ष और भयावह होगा। प्रकृति प्रतिशोध नहीं लेती,वह केवल अपना संतुलन वापस मांगती है। जब मनुष्य उसकी सीमाएं लांघता है,तब प्रकृति उसे उसकी अपनी सीमाओं का अहसास करा देती है। इसलिए विकास को प्रकृति-विरोधी नहीं,बल्कि प्रकृति-संगत बनाना अब विकल्प नहीं,राष्ट्रीय आवश्यकता है। देश के वन-सीमांत गांव एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। बावनगजा से लेकर कोडागु और पश्चिमी घाट तक एक ही पुकार है—जंगल बचेंगे तो गांव बचेंगे, गांव बचेंगे तो किसान बचेगा और किसान बचेगा तो भारत बचेगा। मनुष्य और वन्यजीवों का यह संघर्ष किसी एक की जीत से नहीं थमेगा। इसका समाधान केवल संतुलन,सह-अस्तित्व और इस स्वीकार में है कि धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का है,उतना ही जंगल के हर जीव का भी।

जो मर नहीं सकता...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

नगर के बीचों-बीच एक सुबह खबर फैली कि ईमानदारी मर गई। लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि ईमानदारी को आख़िरी बार किसी ने देखा ही कब था? थानेदार बोला,पहले पहचान तो कर लो कि मरने वाली सचमुच ईमानदारी ही है या कोई और। नेता जी बोले,हमारी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे नेता बोले,अगर संबंध निकल आया तो पहली पार्टी ज़िम्मेदार होगी। तीसरे नेता बोले,जाँच होनी चाहिए। चौथे नेता बोले,जाँच समिति बनाने के लिए भी एक समिति बननी चाहिए। नगरपालिका ने लाश उठाने से मना कर दिया। कारण पूछा गया। अधिकारी बोला, ईमानदारी हमारे विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। लाश सड़क पर पड़ी रही। लोग सेल्फ़ी लेते रहे। कुछ ने श्रद्धांजलि दी। कुछ ने रील बनाई। कुछ ने लिखा, बहुत दुखद। और पोस्ट डालते ही हँसने लगे। व्यापारी बोले, ईमानदारी मर गई तो बाज़ार पर असर पड़ेगा। मुनीम बोला,नहीं मालिक,हमारे यहाँ तो पहले से स्टॉक खत्म था। एक पत्रकार पहुँचा। उसने पूछा,मृतका का नाम? किसी को पता नहीं था। उम्र? किसी को याद नहीं थी। पता? सबने कहा, बहुत साल पहले इसी शहर में रहती थी। पत्रकार ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। देश को हिला देने वाली खबर! देश नहीं हिला। हाँ,चैनल का टीआरपी मीटर ज़रूर हिल गया। पोस्टमार्टम का फैसला हुआ। डॉक्टर ने दस्ताने पहने। फिर उतार दिए। बोला,ईमानदारी को हाथ लगाए बहुत साल हो गए हैं, एलर्जी हो सकती है रिपोर्ट आई। मौत का कारण...अत्यधिक उपेक्षा। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। एक बुज़ुर्ग ने दावा किया कि उसने हत्या होते देखी है। भीड़ जमा हो गई। बुज़ुर्ग बोला,हत्यारे कई थे। कौन? लालच। और? सुविधा। और? समझौता। और? चुप्पी। लोग निराश हो गए। उन्हें किसी एक आदमी का नाम चाहिए था। अपने-अपने नाम नहीं। जाँच आयोग बैठा। आयोग ने तीन साल तक जाँच की। फिर निष्कर्ष निकाला...ईमानदारी की मौत हुई है या नहीं,यह कहना जल्दबाज़ी होगी। आयोग भंग हो गया। फिर दूसरा आयोग बना। उधर शहर में चुनाव आ गए। हर नेता ने घोषणा की...अगर हम जीत गए तो ईमानदारी को वापस जिंदा कर देंगे। जनता ने ताली बजाई। जनता को हमेशा से जादू पसंद था।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

C M Y K

औचक निरीक्षण के बाद डीईओ ने बढ़ाई जवाबदेही

अनुपस्थित कर्मचारियों का मानदेय रोकने के निर्देश

कई स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारने का दिया आदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।
जिले के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं का जायजा लेने शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने अंबिकापुर विकासखंड के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति, अधूरा गणवेश व पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वच्छता की कमी तथा निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आई। वहीं जहां व्यवस्थाएं बेहतर मिलीं, वहां शिक्षकों के कार्य की सराहना भी की गई। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों का मानदेय रोकने और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण की शुरुआत प्राथमिक शाला नवापारा से हुई। यहां दर्ज 24 विद्यार्थियों में केवल चार उपस्थित मिले। गणवेश वितरण और पाठ्यपुस्तकों की स्कैनिंग का कार्य अधूरा मिला। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की कमी और भवन के जर्जर हिस्सों पर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय रसोइया और स्वीपर अनुपस्थित मिलने पर दोनों का मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सेजेस विद्यालय गांधीनगर का निरीक्षण किया गया। यहां सभी शिक्षक उपस्थित मिले और कक्षाएं नियमित संचालित होती पाई गईं। हालांकि पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय का भृत्य अनुपस्थित मिलने पर उसे निरीक्षण दिवस के लिए अनुपस्थित दर्ज करने को कहा गया।

भगवानपुर में कम रही छात्र उपस्थिति

प्राथमिक शाला भगवानपुर में 49 में से केवल 12 विद्यार्थी उपस्थित मिले। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई, लेकिन विद्यालय भवन की मरम्मत और पुताई की आवश्यकता महसूस की गई। प्रधान पाठक को शाला विकास निधि से तत्काल पुताई कराने तथा बड़े मरम्मत कार्यों का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। यहां भी सहायिका और स्वीपर अनुपस्थित मिलने पर उनका मानदेय रोकने के आदेश दिए गए।

असामाजिक तत्वों की शिकायत पर एसपी से चर्चा

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर में कक्षाएं नियमित संचालित मिलीं। व्याख्याता ज्योति सिन्हा के अध्यापन कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी ने सराहना की। विद्यालय के प्राचार्य ने लिपिकीय स्टाफ की कमी और स्कूल परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से अवगत कराया। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। वहीं शासकीय हाई स्कूल अजीरमा में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर शिक्षकों के कार्य की प्रशंसा की गई।

केशवपुर स्कूल में मिलीं कई कमियां

सेजेस विद्यालय केशवपुर में निरीक्षण के दौरान स्वच्छता का अभाव, टूटी खिड़कियां, क्षतिग्रस्त डस्टबिन और गमले मिले। 16वें वित्त आयोग से स्वीकृत शौचालय और बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। कई शिक्षक अवकाश पर थे तथा विद्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण भी कमजोर नजर आया। जिला शिक्षा अधिकारी ने शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने और आवश्यक परीक्षण के बाद स्वीकृत राशि जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण का उद्देश्य,शैक्षणिक गुणवत्ता

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने बताया कि उनके निर्देशन में जिले के सभी जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों तथा संकुल केंद्र समन्वयकों ने भी अपने-अपने अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

11 साल पुराने जमीन विवाद में फिर बढ़ा तनाव

कब्जा नहीं मिलने से खेत समतल कराने पहुंचे ग्रामीण विवाद में महिला से मारपीट,कलाई पर काटा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम परसा में 11 साल पुराने जमीन विवाद में न्यायालय का फैसला आने के बाद भी कब्जा नहीं मिलने से एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद ग्रामीण खेती की तैयारी के लिए जमीन समतल कराने पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान एक महिला की कलाई दांत से काट दी गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों के अनुसार गांव के 32 लोगों की करीब 24-25 एकड़ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वे पिछले 11 वर्षों से न्यायालय में प्रकरण लड़ रहे थे। 15 जून को नायब तहसीलदार न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद राजस्व अमले को पुलिस की मौजूदगी में कब्जा दिलाने की कार्रवाई करनी थी, लेकिन दस दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्वयं न्यायालय का आदेश कोतवाली थाने में जमा कराया था और उसकी पावती भी न्यायालय में प्रस्तुत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर वे खेती की तैयारी के लिए जेसीबी से जमीन समतल कराने पहुंचे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध करते हुए विवाद शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से विवाद की स्थिति बनी।

महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज : ग्राम परसा महादेवपारा निवासी सोनम महंत ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 26 जून को वह अपने परिवार के साथ खेत में मकई की बुआई कराने गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि विवाद के दौरान विनोद नामक व्यक्ति ने उनकी बाईं कलाई दांत से काट ली, जिससे उन्हें चोट आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाने में पहुंचे ग्रामीण, ड्यूटी अफसर को नहीं थी जानकारी : शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर कोतवाली थाना पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई के बजाय दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात कही गई। वहीं, थाने में मौजूद ड्यूटी अफसर से जब ग्रामीणों की मौजूदगी का कारण पूछा गया तो उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

पीलिया से जंग जीतकर ड्यूटी पर लौटे आरक्षक की जिंदगी की जंग में हार,सरकारी क्वार्टर में मिली लाश...मौत के कारणों पर सस्पेंस

राजपुर थाना परिसर में पसरा मातम,आरक्षक जुगन साय पैकरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच

-संवाददाता-
राजपुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना परिसर में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई,जब थाना परिसर में रहने वाले एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। थाना परिसर स्थित शासकीय क्वार्टर में रहने वाले आरक्षक जुगन साय पैकरा अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले। घटना के बाद पूरे थाना परिसर में शोक का माहौल है। साथी जवान और पुलिस अधिकारी इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध हैं। राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि आरक्षक जुगन साय पैकरा थाना परिसर में बने सरकारी आवास में रहते थे। शुक्रवार रात करीब 9 बजे वह रोज की तरह अपने कमरे में सोने चले गए थे। शनिवार सुबह काफी देर तक जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों को चिंता हुई। साथियों ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो आरक्षक जुगन साय पैकरा अचेत अवस्था में पड़े मिले। तत्काल उन्हें संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया।

बीमारी से उबरकर दोबारा संभाली थी ड्यूटी

बताया जा रहा है कि आरक्षक जुगन साय पैकरा कुछ माह पहले पीलिया (जॉन्डिस) बीमारी से पीड़ित हुए थे। बीमारी के दौरान उन्होंने उपचार कराया और स्वस्थ होने के बाद दोबारा अपनी नियमित पुलिस ड्यूटी संभाल ली थी। उनके अचानक निधन से पुलिस विभाग और परिजनों को गहरा झटका लगा है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मौत किसी पुरानी बीमारी के कारण हुई है या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है। बीमारी से ठीक होकर ड्यूटी पर लौटे जवान की अचानक मौत ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

महापौर के कथित रिश्वत ऑडियो मामले में सियासत तेज,कांग्रेस ने SIT जांच की मांग उठाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।
नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत के नाम से कथित रूप से वायरल हुए रिश्वत मांगने वाले ऑडियो मामले को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मामले में महापौर मंजूषा भगत ने अनुविभागीय अधिकारी (अजा/जजा) थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन में महापौर की ओर से कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बाजार आवंटन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया,जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले की जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अजा/जजा थाना पहुंचा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर की जनता इस ऑडियो को लेकर भ्रमित है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार थाना प्रभारी ने प्रारंभिक चर्चा में बताया कि आवेदन उनके थाना क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर आवेदन पुलिस अधीक्षक को भेजकर संबंधित थाना क्षेत्र में जांच के लिए अग्रेषित करने पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता अनूप मेहता ने बताया कि महापौर मंजूषा भगत के आवेदन पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है,जिसके बाद रविवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय दिया गया है। कांग्रेस इस मामले में स्ट्रङ्क (विशेष जांच दल) गठन की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि शहर की प्रथम नागरिक द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने पहल की है। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाना गलत है कि कांग्रेस महापौर को बदनाम कर रही है। भाजपा शासित नगर निगम और उसके पदाधिकारी स्वयं ही विवादों के कारण चर्चा में आ रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

गांधी चौक में खुलेआम भिड़े दो गुट,तमाशबीन बनी रही भीड़

सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था, चौक की 'तीसरी आंख' भी रही बेअसर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।
शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल गांधी चौक में दिनदहाड़े दो गुटों के बीच जमकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। बीच चौराहे पर हुए इस घटनाक्रम ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया हैं। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे, जबकि कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और सड़क पर ही धक्का-मुक्की व हाथापाई शुरू हो गई। व्यस्त चौक पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के प्रमुख चौक पर लगे निगरानी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो गई। क्या अपराधियों में पुलिस और कानून का भय खत्म हो रहा है? गांधी चौक जैसे संवेदनशील स्थान पर खुलेआम हुई इस घटना ने शहरवासियों में चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर ही इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता की टीम की फिर कार्रवाई,सूरजपुर से 42 नशीले इंजेक्शन जब्त

■ एक के बाद एक गिरफ्तारी...फिर भी सवाल बरकरार...आखिर इन सौदागरों तक माल पहुंचा कौन रहा है?

■ सरगुजा से सूरजपुर तक फैला नेटवर्क...छोटे विक्रेता पकड़ में लेकिन बड़े सप्लायर अब भी पहुंच से बाहर...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार के खिलाफ संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन माने जाने वाले रंजीत गुप्ता की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को सूरजपुर जिले में एक बार फिर कार्रवाई करते हुए टीम ने कथित नशीले इंजेक्शन विक्रेता प्रदीप राजवाड़े को 42 नग इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। आबकारी विभाग के अनुसार यह कार्रवाई सूरजपुर जिले के थाना जय नगर क्षेत्र में की गई। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महुआरी अरसोता जंगल में एक व्यक्ति नशीले इंजेक्शन बेच रहा है। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान प्रदीप राजवाड़े निवासी कमलापुर थाना विश्रामपुर के रूप में हुई। उसके पास मौजूद कपड़े के थैले की तलाशी लेने पर 21 नग REXOGESIC और 21 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

कार्रवाई लगातार,लेकिन नशे की सप्लाई लाइन अब भी सवालों में...

- सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम द्वारा लगातार नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- पहले अम्बिकापुर में वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी।
- फिर कथित सप्लायर मोशीम अंसारी से बड़ी मात्रा में इंजेक्शन बरामदगी।
- इसके बाद लुंड्रा क्षेत्र से कथित सप्लायरों पर कार्रवाई।
- और अब सूरजपुर में प्रदीप राजवाड़े की गिरफ्तारी।
- लगातार सामने आ रहे मामले यह बताते हैं कि नशीले इंजेक्शनों का नेटवर्क केवल एक जगह तक सीमित नहीं है।

लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी कायम है...

- इन छोटे विक्रेताओं तक नशीली दवाइयां पहुंच कौन रहा है?
- बड़े सौदागर अब भी जांच के दायरे से बाहर?
- हर कार्रवाई में एक नया आरोपी सामने आता है।
- कुछ इंजेक्शन बरामद होते हैं।
- आरोपी जेल भेज दिया जाता है।
- लेकिन जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब भी अधूरी दिखाई देती है।
- नशीले इंजेक्शन आखिर किस चैनल से निकलकर इन विक्रेताओं तक पहुंच रहे हैं?
- कौन है वह सप्लाई करने वाला नेटवर्क?
- कौन लोग इस अवैध कारोबार से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं?
- इन सवालों का जवाब सामने आना बाकी है।

सुपरमैन रंजीत गुप्ता ने माना, सूरजपुर में सक्रिय हैं सौदागर

सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता ने बताया कि आसपास के सभी जिलों में नशे के सौदागरों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिले में यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उनका यह बयान इस बात की ओर भी इशारा करता है कि नशीले इंजेक्शनों का नेटवर्क अब केवल अम्बिकापुर तक सीमित नहीं है,बल्कि आसपास के जिलों तक फैल चुका है।

गद्दवा कनेक्शन से लेकर स्थानीय नेटवर्क तक

पिछले मामलों में सप्लाई चैन के तार बाहरी क्षेत्रों से जुड़ने की बात सामने आई थी। विभाग ने संसाधनों की कमी और अंतरराज्यीय कार्रवाई की कठिनाइयों का भी उल्लेख किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि स्थानीय स्तर पर इतने विक्रेता सक्रिय हैं तो इनके पीछे काम कर रही सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए क्या विशेष रणनीति बनाई गई है?

महुआ शराब से इंजेक्शन तक... नशे के खिलाफ बड़ी चुनौती...

- सरगुजा संभाग में अवैध नशे का स्वरूप लगातार बदल रहा है।
- कहीं महुआ शराब का अवैध निर्माण पकड़ा जा रहा है।
- कहीं होटल और अन्य स्थानों से शराब बिक्री सामने आ रही है।
- और अब नशीले इंजेक्शनों का नेटवर्क लगातार सामने आ रहा है।
- इससे साफ है कि चुनौती केवल कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की है।

जनहित के सवाल...

- 42 इंजेक्शन लेकर घूम रहा आरोपी माल कहां से ला रहा था?
- उसके पीछे सप्लायर कौन है?
- क्या जब्त इंजेक्शनों के बैच नंबर की जांच होगी?
- क्या मेडिकल सप्लाई चैन की जांच की जाएगी?
- क्या बड़े कारोबारियों और आर्थिक नेटवर्क तक कार्रवाई पहुंचेगी?
- लगातार गिरफ्तारियों के बाद भी नशीले इंजेक्शन बाजार तक कैसे पहुंच रहे हैं?

आबकारी अभियान की अगली परीक्षा

सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में आबकारी उड़नदस्ता टीम की लगातार कार्रवाई से छोटे स्तर के विक्रेताओं पर दबाव जरूर बना है, लेकिन नशे के खिलाफ असली लड़ाई तब सफल मानी जाएगी जब सप्लाई की मूल कड़ी तक पहुंच बनाई जाएगी।

क्योंकि हर गिरफ्तारी के बाद एक ही सवाल फिर खड़ा हो रहा है...

सौदागर पकड़े जा रहे हैं,लेकिन नशे का असली कारोबारी कौन है?

अकीदत,अमन और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ मोहर्रम पर्व

सूरजपुर में निकले पारंपरिक ताजिया जुलूस,कर्बला में धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ समापन

-संवाददाता-

सूरजपुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मोहर्रम पर्व शुक्रवार को सूरजपुर जिले में पूरी अकीदत, अमन और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ, नगर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाले गए,जिनका समापन कर्बला में धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया,पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक आस्था,अनुशासन और सामाजिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण देखने को मिला।

नगर के प्रमुख मार्गों से निकले ताजिया जुलूस- सूरजपुर नगर के मस्जिद पारा, महगांव,मानपुर,मिलपारा और नवापारा सहित विभिन्न मोहल्लों से पारंपरिक ताजिए निकाले गए,जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नवापारा पहुंचा,जहां निर्धारित धार्मिक कार्यक्रमों के बाद सभी ताजियों को वापस कर्बला लाया गया और पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार ठंडा किया गया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा और अनुशासन के साथ भाग लिया।

युवाओं ने दिखाए पारंपरिक युद्धक कौशल- मोहर्रम जुलूस के दौरान युवाओं ने लाठी, तलवार और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ युद्धक कलाओं का आकर्षक प्रदर्शन किया,विभिन्न प्रकार के हैरतअंगेज करतबों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में मौजूद नागरिकों ने इन प्रदर्शनों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, युवाओं ने अनुशासन और परंपरा का उत्कृष्ट परिचय देते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

शरबत और पानी वितरण से दिया सेवा का संदेश

जुलूस मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों,व्यापारियों और नागरिकों ने श्रद्धालुओं के लिए शरबत,ठंडा पानी तथा अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था की,भीषण गर्मी के बावजूद सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवकों ने मानवता और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की,राहगीरों और जुलूस में शामिल लोगों ने इस सेवा भावना की सराहना की।

प्रशासन रहा पूरी तरह सतर्क

मोहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था,जबकि जुलूस के पूरे मार्ग पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे, प्रशासन की सतर्कता और नागरिकों के सहयोग से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

नौ दिनों तक गूंजता रहा इमाम हुसैन का जिक्र

मोहर्रम के अवसर पर जिले की विभिन्न मस्जिदों और इमामबाड़ों में लगातार नौ दिनों तक मजलिसों का आयोजन किया गया, उलेमा-ए-किराम ने अपने संबोधन में हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानी, इंसाफ, सत्य, मानवता और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला,अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत कर इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को खिराज-ए-अकीदत पेश किया।

त्याग और भाईचारे का संदेश...

मोहर्रम का पर्व एक बार फिर यह संदेश देकर संपन्न हुआ कि सत्य, न्याय, त्याग और मानवता की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा, धार्मिक आस्था, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुए इस आयोजन ने जिले में एकता और सौहार्द की मजबूत मिसाल प्रस्तुत की।

दुष्कर्म आरोपी पशु चिकित्सक पर कार्रवाई में देरी,खबर प्रकाशित होते ही उप संचालक को थमाया कारण बताओ नोटिस

48 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बावजूद निलंबन प्रस्ताव समय पर नहीं भेजने पर संचालक ने मांगा तीन दिन में जवाब

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

दुष्कर्म के आरोपी पशु चिकित्सक पर विभागीय कार्रवाई में देरी का मामला सामने आने के बाद अब पशु चिकित्सा विभाग ने सरगुजा के प्रभारी उप संचालक डॉ. आरपी शुक्ला को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि आरोपी अधिकारी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बावजूद नियमानुसार समय पर जानकारी और निलंबन संबंधी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा 11 जून 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि गांधीनगर थाना में डॉ.

संजीवन टोप्पो के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज होने तथा 16 मई 2026 को गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस ने इसकी सूचना 20 मई को कार्यालय को भेज दी थी, जो 21 मई को प्राप्त हो गई थी। इसके बावजूद उप संचालक कार्यालय द्वारा इसकी जानकारी मुख्यालय को 5 जून 2026 को भेजी गई। नोटिस में कहा गया है कि यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 के विपरीत है। नियमानुसार यदि कोई शासकीय सेवक 48 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो उसे निलंबित माना जाता है और इसकी तत्काल सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

पहले क्या था मामला : गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर डॉ. संजीवन टोप्पो के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था। करीब डेढ़ माह बाद उन्हें जमानत मिली। इस बीच उनके निलंबन में हुई देरी को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई थी।

12 दिन के भीतर दूसरी बार नोटिस : पशुधन विकास विभाग सरगुजा के प्रभारी उपसंचालक डॉ. आरपी शुक्ला को 12 दिन के भीतर दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बार मामला प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं (पीएआईडब्ल्यू) के मानदेय भुगतान में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर ने तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार संचालक कार्यालय ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के पीएआईडब्ल्यू के लंबित मानदेय की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में डॉ. शुक्ला ने दोनों वर्षों का लंबित भुगतान शून्य बताया तथा वर्ष 2024-25 के लिए 5.40 लाख रुपए की मांग भेजी। मांग के अनुरूप विभाग ने उक्त राशि आबंटित भी कर दी। आरोप है कि वर्ष 2024-25 के लिए मिली राशि में से 1.14 लाख रुपए का भुगतान वर्ष 2023-24 के कार्यों के लिए कर दिया गया, जबकि पूर्व में संबंधित अवधि का कोई भुगतान लंबित नहीं होने की जानकारी विभाग को भेजी गई थी। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संचालक ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) के विपरीत माना है। इसी आधार पर 23 जून को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

ससुराल की प्रताडऩा से तंग महिला ने पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान

शव पर मिले चोट के निशान,मायके पक्ष ने पति समेत चार पर लगाए प्रताडऩा के आरोप

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुराल की कथित प्रताडऩा से परेशान एक विवाहिता ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान सीमा यादव (परिवर्तित नाम) के रूप में हुई है। उसका विवाह करीब चार वर्ष पूर्व देवगढ़ निवासी सतीश यादव से हुआ था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ससुराल में प्रताडऩा झेल रही थी। घटना वाले दिन वह गांव के पास एक बड़े पेड़ पर चढ़ी और फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के शव पर चोट के निशान मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। मायके पक्ष ने पति,सास,ससुर और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता का कहना है कि बेटी अक्सर प्रताडऩा की शिकायत करती थी, लेकिन सामाजिक मान-मर्यादा के कारण उसे समझाकर ससुराल में ही रहने की सलाह देते रहे। घटना की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। उदयपुर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम अंबिकापुर सहित सीतापुर व लखनपुर के नवनियुक्त एल्डरमैनों का भाजपा ने किया सम्मान

जनहित के मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाएं,नगरीय समस्याओं के समाधान में निभाएं भूमिका : राजेश अग्रवाल

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर निगम अंबिकापुर तथा नगर पंचायत सीतापुर एवं लखनपुर में नियुक्त किए गए नवनियुक्त एल्डरमैनों का भाजपा जिला सरगुजा द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त नामांकित पार्षदों को पुष्पगुच्छ, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी के विशिष्ट आतिथ्य तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान नगर निगम अंबिकापुर के नवनियुक्त 9 एल्डरमैनों करताराम गुप्ता, राज बहादुर शास्त्री, श्रीमती सावित्री जायसवाल, संतोष दास, रमेश जायसवाल, तेजिंदर बग्गा, श्रीमती किरण सोनी, शरद सिन्हा एवं श्रीधर केशरी का सम्मान किया गया। वहीं नगर पंचायत सीतापुर के नेमलाल गुप्ता, श्रीमती अमृता पैकरा एवं अनेश्वर गुप्ता तथा नगर पंचायत लखनपुर के दिनेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता एवं मालती कश्यप को भी सम्मानित किया गया।

जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं एल्डरमैन : राजेश अग्रवाल

मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल ने नवनियुक्त एल्डरमैनों को बधाई देते हुए कहा कि शासन ने उन्हें नगरीय निकायों में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि एल्डरमैन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण और सक्रिय भागीदारी से अपनी पहचान

बनाएं। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और जनसमस्याओं के समाधान के लिए एल्डरमैन सदन में जनता की आवाज को मजबूती से रखें।

दायित्व सेवा का माध्यम है : अखिलेश सोनी

भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि भाजपा संगठन में मिलने वाला हर दायित्व सेवा का माध्यम होता है,सम्मान का नहीं। उन्होंने कहा कि एल्डरमैन पार्षदों और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

जनता और शासन के बीच सेतु बनें एल्डरमैन : भारत सिंह सिसोदिया

भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि संगठन हमेशा कार्यकर्ताओं के समर्पण और निष्ठा का सम्मान करता रहा है। उन्होंने कहा कि एल्डरमैन का पद जनता और शासन के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करने का अवसर है। सभी नवनियुक्त एल्डरमैन जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए नगरीय विकास में अपना योगदान दें। कार्यक्रम को महापौर मंजूषा भगत,पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, पूर्व सभापति त्रिलोक कपूर कुशवाहा,जिला महामंत्री अरुणा सिंह,जिला उपाध्यक्ष विकास पांडेय एवं दिनेश साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया,जबकि जिला कोषाध्यक्ष निश्चल प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया। समारोह में भाजपा के पदाधिकारी,कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दिल्ली के जनजातीय सांस्कृतिक समागम से लौटे प्रतिनिधियों का पारंपरिक गोड़ धोनी से सम्मान

सरगुजा में गूंजा जनजातीय स्वाभिमान का स्वर,प्रतिनिधियों का आत्मीय अभिनंदन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में सहभागिता कर लौटे सरगुजा के प्रतिनिधियों का उरांव सामाजिक भवन,पटेलपारा में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जनजाति सुरक्षा मंच,सरगुजा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा एवं बाबा कार्तिक उरांव के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इसके बाद जनजातीय परंपरा के अनुसार पारंपरिक गोड़ धोनी कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेशराम भगत ने कहा कि जनजातीय समाज की पैर धोने की परंपरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि सम्मान,सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार जागरूकता अभियान जारी रखेगा। उन्होंने डीलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि आगामी 29 अक्टूबर को बाबा कार्तिक उरांव जयंती के अवसर पर अंबिकापुर में डीलिस्टिंग गर्जना महारैली आयोजित की जाएगी। गणेशराम भगत ने समाज के लोगों से भगवान बिरसा मुंडा,बाबा कार्तिक उरांव और संत गहिरा गुरु के विचारों पर चलने तथा जनजातीय संस्कृति एवं

अधिकारों के संरक्षण के लिए जनजागरण करने का आह्वान किया। प्रांत सह संयोजक इन्दर भगत ने कहा कि दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम जनजातीय एकता,संस्कृति,अस्मिता और अधिकारों के संरक्षण का बड़ा मंच बना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में देशभर से बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए,जिसमें सरगुजा क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही। उन्होंने कहा कि गोड़ धोनी कार्यक्रम हमारी परंपरा,सम्मान और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। दिल्ली से लौटे प्रतिनिधियों का सम्मान समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने वाला आयोजन है। कार्यक्रम का संचालन जिला संयोजक बिहारीलाल उरांव ने किया,जबकि आभार प्रदर्शन जिला सह संयोजक रज्जू राम ने किया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, वरुण अग्रवाल, पिता श्री राकेश गर्ग, निवासी हाउस न. 110 वार्ड नं. 17 सांवरिया ड्रेसेस, जोड़ा पीपल, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम 'वरुण अग्रवाल' अंकित है, जबकि मेरी कक्षा 10 वीं और 12 वीं की अंकसूची में मेरा नाम 'वरुण गर्ग' अंकित है।

यह कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम 'वरुण अग्रवाल' है तथा भविष्य में मैं सभी सरकारी, शैक्षणिक एवं अन्य आधिकारिक अभिलेखों में 'वरुण अग्रवाल' नाम से ही जाना, पहचाना एवं अभिलेखित किया जाता है।

अतः संबंधित सभी विभागों एवं प्राधिकरणों से अनुरोध है कि मेरे सभी वर्तमान एवं भविष्य के अभिलेखों में मेरा नाम 'वरुण अग्रवाल' ही दर्ज किया जाए।

शपथग्रहिता
वरुण अग्रवाल

Name Modification notice

I am Varun Agrawal son of Rakesh Garg, HOUSE NO. 110 WARD NO. 17 sawariya dresses joda pipal Ambikapur District Sarguja. I am informing that my name in Aadhaar card is Varun agrawal. Whereas in 10th & 12th mark sheet it is Varun garg. Hence, my name is Varun Agrawal, And I am To be known and recognized by name. It should be recorded by this name in all government documents.

Varun Agrawal
Son of Rakesh Garg
Ambikapur,District Sarguja

कार्यालय अधीक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर ,मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण तिथि -24.06.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें https://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग - स.क्रं. 01.02 पत्थलगांव,स.क्र. 03.04 जशपुर, स.क्रं. 05.06 अम्बिकापुर एवं स.क्र. 07.08 सूरजपुर संभाग
03. स.क्रं. 01 'स' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार एवं स.क्र. 02 से 08-'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - स.क्र. 1 से 4-09/07/2026 एवं सं.क्रं. 3 सं 8-15/07/2026

सरल क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	107	जिला जशपुर के ग्राम पंचायत तिलडेगा मुख्य मार्ग से भदरापारा होते हुए कंटगतराई पहुंच मार्ग लंबाई 2.30 कि.मी. का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	191.32
2	108	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं. 1 पत्थलगांव के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण मार्गो में डब्ल्यू.एम.एम., इमलशन, बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	25.00
3	109	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कुनकुरी के अंतर्गत विभिन्न मार्गो एवं पुल पुलियों का साधारण मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	25.00
4	110	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कुनकुरी के अंतर्गत विभिन्न मार्गो एवं पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	50.00
5	111	शासकीय पी जी कॉलज अम्बिकापुर में स्वशासी प्रकोष्ठ में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	24.58
6	112	जिला सरगुजा में जिला ई-लाईब्रेरी अम्बिकापुर के प्रथम तल का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	31.41
7	113	शासकीय रेशम केन्द्र मेण्ड्रा विकासखण्ड प्रेमनगर जिला सरगुजा में कृमिपालन भवन का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	17.04
8	114	जिला सूरजपुर में सहायक कृषि यंत्री कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	50.04

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर,मण्डल अम्बिकापुर

जी0नं0 -262701727/2

मोबाइल और रुपये नहीं देने पर मारपीट

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)।

लघुशंका कर रहे युवकों से मोबाइल और रुपये की मांग करते हुये बाइक सवारों के द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, रिपोर्ट पर पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सहनपुर निवासी अंश दुबे ने पुलिस को बताया है कि 24 जून को वह अपने दोस्त विवेक कुमार भगत के साथ बजाज प्लेटिना मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 ईई 8854 में अंबिकापुर से अपने निवास स्थान सहनपुर वापस जा रहा था। रास्ते में शाम करीब 7 बजे ग्राम बिशुनपुर डामर प्लांट के पास मोटरसायकल को रोककर लघुशंका कर रहे थे, तभी पीछे से बजाज प्लसर मोटरसायकल में दो लोग तेज रफ्तार में पहुंचे और इनसे पैसा और मोबाइल मांगने लगे। इनकी बात नहीं मानने पर एक अन्य व्यक्ति डण्डा लेकर आया और गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे। इस दौरान भयभीत होकर विवेक भगत वहां से भाग गया। मारपीट में अंश दुबे को चोट आई है। पूछताछ करने पर पता चला कि मारपीट करने वाले ग्राम मंगारी के अनिल बादी, सूरज बादी सहित अन्य थे। ईलाज कराने के बाद युवक ने सीतापुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है,जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

नौगाई हत्याकांड:
क्या केवल एक सब-इंस्पेक्टर पर कार्रवाई से पूरी पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही तय हो जाएगी?

- **लापरवाही किसकी?** थाना प्रभारी ने संवेदनशील स्थिति में थाना क्यों छोड़ा?
- **समझौता या साजिश?** क्या समझौते की कोशिश ने बढ़ाई लापरवाही?
- **आत्मसमर्पण की कहानी पर सवाल** क्या पुलिस गिरफ्तारी में नाकाम रही?
- **कई अधिकारियों की भूमिका पर संदेह** CDR जांच और विभागीय जांच की मांग तेज

पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगें

- विधायक और थाना प्रभारी के बीच बातचीत की CDR जांच हो
- मनेंद्रगढ़ प्रधान आरक्षक के CDR की भी जांच हो
- थाना प्रभारी, सब-इंस्पेक्टर सहित सभी की भूमिका की जांच हो
- लापरवाही या साजिश पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो

नौगाई हत्याकांड : क्या केवल एक सब-इंस्पेक्टर पर कार्रवाई से पूरी पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही तय हो जाएगी?

नौगाई हत्याकांड में बढ़े जवाबदेही के सवाल...क्या विभागीय जांच पूरी कमांड चेन तक पहुंचेगी?

- सब-इंस्पेक्टर हटे...लेकिन असली सवाल बाकी: घटना रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी?
- नौगाई हत्याकांड में लापरवाही...कथित आत्मसमर्पण और पुलिस की भूमिका पर उठे नए सवाल
- क्या नौगाई हत्याकांड रोका जा सकता था? पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल...
- एक अधिकारी पर कार्रवाई या पूरी व्यवस्था की जांच? नौगाई हत्याकांड में जवाबदेही की नई बहस
- क्या विभागीय जांच थाना प्रभारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी?

लापरवाही किसकी थी? नौगाई हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर उठ रहे गंभीर सवाल

आत्मसमर्पण की कहानी, लापरवाही के आरोप और जांच की मांग—नौगाई हत्याकांड में खुलते नए सवाल

सब-इंस्पेक्टर को हटाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कथित आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष विभागीय जांच की मांग उठाई...

कई अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग तेज,पीड़ित परिवार ने उच्चस्तरीय जांच की मांग दोहराई

-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी,27 जून 2026 (घटती-घटना)। नौगाई तिहरे हत्याकांड ने केवल एक जघन्य आपराधिक घटना के रूप में ही नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था,प्रशासनिक निर्णयों और जवाबदेही की पूरी प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं,घटना के बाद से अब तक कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं,इसी बीच सब-इंस्पेक्टर राजाराम राठिया को सोनहत से हटाए जाने की खबर सामने आने के बाद एक नया सवाल पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा है क्या इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी केवल एक अधिकारी तक सीमित कर दी जाएगी, या फिर उन सभी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी जिनके निर्णयों, लापरवाही या कथित निष्क्रियता ने इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार की? सूत्रों के अनुसार सब-इंस्पेक्टर राजाराम राठिया के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है, यदि ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से पुलिस विभाग की एक कार्रवाई होगी, लेकिन इससे कहीं बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विभाग केवल उसी अधिकारी तक सीमित रहेगा जो कुछ घंटों के लिए थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत था, या फिर वास्तविक थाना प्रभारी, वरिष्ठ अधिकारियों और पूरे कमांड सिस्टम की भूमिका की भी समान गंभीरता से समीक्षा की जाएगी?

क्या केवल कुछ घंटों का प्रभार पूरी जिम्मेदारी तय कर देता है?

घटना के दिन वास्तविक थाना प्रभारी शाम तक अपने थाना क्षेत्र में मौजूद थे,इसके बाद उन्होंने थाने का प्रभार एक सब-इंस्पेक्टर को सौंप दिया ऐसा कहा जा रहा है, इसी अवधि में क्षेत्र में तनाव बढ़ता गया और देर रात वह भयावह घटना घट गई, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, यहीं से पहला बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, यदि पुलिस को पहले से गांव में विवाद,तनाव और संभावित हिंसा की आशंका की जानकारी थी, तो क्या ऐसी परिस्थिति में थाना प्रभारी विनोद पासवान को थाना छोड़ना चाहिए था? क्या संवेदनशील हालात में वरिष्ठ अधिकारी का स्वयं मौके पर मौजूद रहना पुलिसिंग का सामान्य सिद्धांत नहीं माना जाता? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घटना अचानक नहीं हुई थी, ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव था और घटना से पहले भी विवाद की जानकारी पुलिस तक पहुंच चुकी थी।,यदि यह तथ्य जांच में प्रमाणित होता है तो यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत जवाबदेही का विषय बन सकता है।

समझौते की कोशिश या कानून-व्यवस्था की अनदेखी?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा लगातार होती रही है कि घटना से पहले पुलिस की प्राथमिकता दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने पर अधिक केंद्रित थी, जबकि दूसरी ओर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा था, यदि पुलिस वास्तव में समझौते की प्रक्रिया में लगी थी तो यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त महत्व दिया गया था? क्या संभावित हिंसा रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया? क्या किसी पक्ष से हथियार या हमले की आशंका का आकलन किया गया? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर पूरी जानकारी दी गई? ये सभी प्रश्न केवल अनुमान नहीं बल्कि विभागीय जांच का विषय हो सकते हैं, किसी भी संवेदनशील मामले में पुलिस की पहली जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना होती है, यदि बाद में यह स्थापित होता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी तो विभागीय जवाबदेही स्वाभाविक रूप से तय होगी।

क्या पुलिस घटना नहीं चाहती थी, लेकिन लापरवाही ने रास्ता बना दिया?

स्थानीय नागरिकों का बड़ा वर्ग यह मानता है कि पुलिस स्वयं ऐसी घटना नहीं चाहती थी, लेकिन यदि समय पर प्रभावी कदम उठाए जाते,पर्याप्त बल तैनात किया जाता,संवेदनशील गांव में निगरानी बढ़ाई जाती या संभावित आरोपियों पर पहले से नियंत्रण किया जाता,तो संभव है कि यह वारदात टाली जा सकती थी,यही कारण है कि अब बहस केवल अपराधियों तक सीमित नहीं है,बल्कि इस प्रश्न तक पहुंच चुकी है कि क्या यह अपराध पुलिस की कथित लापरवाही के कारण संभव हो सका,यदि जांच में यह सामने आता है कि पुलिस के पास पहले से पर्याप्त सूचना थी और फिर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो विभागीय कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रह सकती।

आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी यह विवाद क्यों बना?

घटना के बाद जिस विषय ने सबसे अधिक चर्चा बटोरी, वह आरोपियों के मनेन्द्रगढ़ में कथित आत्मसमर्पण की कहानी थी, सामान्यतः किसी जघन्य अपराध के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन इस मामले में आत्मसमर्पण की बात सामने आने के बाद अनेक प्रश्न उठने लगे, कानूनी दृष्टि से आत्मसमर्पण का अर्थ यह माना जाता है कि आरोपी स्वयं कानून के समक्ष उपस्थित हुआ, दूसरी ओर गिरफ्तारी का अर्थ है कि पुलिस ने उसे खोजकर विधिवत पकड़ा,यही अंतर इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है,यदि आरोपी वास्तव में पुलिस के दबाव में स्वयं सामने आए,तो परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन यदि आत्मसमर्पण की कहानी प्रशासनिक प्रस्तुति भर थी, तो यह भी जांच का विषय बन सकता है कि वास्तविक घटनाक्रम क्या था?

'बैक डोर' आत्मसमर्पण की चर्चा क्यों?

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया सामान्य तरीके से नहीं हुई,उनका कहना है कि इसकी पटकथा मनेन्द्रगढ़ में एक अधिवक्ता के निवास पर तैयार की गई और बाद में इसे आत्मसमर्पण का स्वरूप दिया गया,हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों ने भी सार्वजनिक रूप से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, फिर भी,चूंकि पीड़ित परिवार स्वयं इस पर सवाल उठा रहा है, इसलिए निष्पक्ष जांच इन आरोपों की सत्यता स्पष्ट कर सकती है।

प्रधान आरक्षक की भूमिका पर भी सवाल-

परिजनों ने एक चर्चित प्रधान आरक्षक की भूमिका पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया है, उनका दावा है कि संबंधित पुलिसकर्मी का आरोपियों के परिवार से किसी प्रकार का पारिवारिक या रिश्तेदारी का संबंध हो सकता है, यह दावा अभी अपुष्ट है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, इसी कारण परिजन चाहते हैं कि संबंधित प्रधान आरक्षक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), लोकेशन और घटना से पहले तथा बाद की गतिविधियों की जांच कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या संदेह का निष्पक्ष समाधान हो सके।

थाना प्रभारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आए?-

सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की चर्चा के साथ-साथ यह मांग भी उठ रही है कि वास्तविक थाना प्रभारी की भूमिका का भी स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए, यदि वे घटना से पहले क्षेत्र में मौजूद थे, तो उन्होंने कौन-कौन से निर्देश दिए? उन्होंने अतिरिक्त बल की मांग की या नहीं? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को क्या जानकारी भेजी? और सबसे महत्वपूर्ण—उन्होंने संवेदनशील समय में थाना छोड़ने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल विभागीय जांच ही दे सकती है।

स्थानीय विधायक से बातचीत की जांच की मांग...

पीड़ित परिवार ने यह भी मांग की है कि घटना वाले दिन स्थानीय विधायक और संबंधित पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का भी परीक्षण किया जाए,यह मांग कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच के रूप में सामने आई है,यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवल किसी जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत होना अपने आप में कोई गलत या अवैध बात नहीं है,लेकिन यदि पीड़ित पक्ष को यह आशंका है कि किसी बातचीत का प्रभाव पुलिस के निर्णयों पर पड़ा,तो ऐसी आशंकाओं को दूर करने का सबसे उचित तरीका निष्पक्ष जांच ही है।

एडिशनल एसपी की भूमिका पर भी उठ रहे प्रश्न

परिजनों ने कोरिया जिले के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों को पहले से तनाव की जानकारी थी तो समय रहते अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और यदि जानकारी नहीं थी,तो यह भी गंभीर प्रशासनिक प्रश्न है, इन आरोपों पर अभी तक संबंधित अधिकारी का सार्वजनिक पक्ष सामने नहीं आया है, इसलिए इस विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि शिकायतें दर्ज हैं, तो विभागीय स्तर पर उनकी समीक्षा होना स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

क्या केवल निलंबन या हटाना पर्याप्त है?

किसी भी बड़ी घटना के बाद प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में अधिकारियों को हटाना, लाइन अटैच करना या निलंबित करना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, लेकिन यदि जांच केवल वहीं समाप्त हो जाए,तो उससे वास्तविक जवाबदेही स्थापित नहीं हो पाती, आवश्यक यह है कि पूरी कमांड चेन की समीक्षा हो,किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया? किसने कौन-सी सूचना किस समय प्राप्त की? किस स्तर पर कार्रवाई में देरी हुई? क्या अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जा सकता था? क्या घटना को रोका जा सकता था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ही भविष्य की पुलिस व्यवस्था को मजबूत बना सकता है।

सरगुजा आईजी और डीजीपी से बढ़ी उम्मीदें...

अब यह मामला केवल एक थाना या एक जिले तक सीमित नहीं रह गया है, पीड़ित परिवार और क्षेत्र के अनेक नागरिक चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निगरानी उच्च स्तर पर हो, उनकी मांग है कि सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक पूरे घटनाक्रम की विभागीय समीक्षा कराएं,ताकि यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो वह सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो,ऐसी जांच केवल इस मामले के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

न्याय केवल आरोपियों की सजा से नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही से भी मिलेगा...

नौगई हत्याकांड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी जघन्य अपराध में केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होती, यदि प्रशासनिक स्तर पर भी चूक हुई है,तो उसकी पहचान और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है,यदि विभागीय जांच निष्पक्ष और व्यापक होती है तो इससे न केवल पीड़ित परिवार का विश्वास मजबूत होगा बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिलेगी,इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा,लेकिन यह निश्चित है कि जब तक हर स्तर की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं होगी,तब तक यह सवाल बना रहेगा कि क्या केवल एक अधिकारी पर कार्रवाई कर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जा सकती है, या फिर इस घटना की कई परतें अभी खुलना बाकी हैं।

छत्तीसगढ़ में साकार हुआ 'मिनी केदारनाथ', सिद्धबाबा धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई प्राण-प्रतिष्ठा

छत्तीसगढ़ में साकार हुआ 'मिनी केदारनाथ', सिद्धबाबा धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई प्राण-प्रतिष्ठा

1200 फीट ऊंचे सिद्धबाबा पहाड़ पर गूंजा 'हर-हर महादेव' केदारनाथ की तर्ज पर बने मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा

6 वर्षों की साधना रंग लाई,मनेंद्रगढ़ के सिद्धबाबा धाम को मिला 'मिनी केदारनाथ' का भव्य स्वरूप

मनेंद्रगढ़ बना नई आस्था का केंद्र... सिद्धबाबा धाम में भव्य प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न

121 वर्ष पुराने सिद्धबाबा धाम का हुआ कायाकल्प,केदारनाथ की तर्ज पर बने मंदिर के खुले पट...

3 करोड़ रुपये की लागत,6 वर्षों में तैयार हुआ भव्य मंदिर,ओडिशा के शिल्पकारों ने दी केदारनाथ जैसी वास्तुकला,शोभायात्रा में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल...

-दीप सिंह-

मनेंद्रगढ़ ,27 जून 2026 (घटती-घटना)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सिद्धबाबा धाम में शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई, लगभग 1200 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस प्राचीन तपोस्थल को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया गया है, प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही यह धार्मिक स्थल अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल हो गया है, तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और प्रयागराज से आए साधु-संतों एवं हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

केदारनाथ की तर्ज पर तैयार हुआ भव्य मंदिर

सिद्धबाबा धाम के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य फरवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, लगभग छह वर्षों तक चले निर्माण कार्य में सिद्धबाबा सेवा समिति एवं जनसहयोग से करीब तीन करोड़ रुपये व्यय किए गए, मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर से प्रेरित है, मंदिर की नक्काशी और पत्थर की कलाकृतियों को आकार देने के लिए ओडिशा के अनुभवी शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने महीनों की मेहनत से इसे आकर्षक स्वरूप प्रदान किया।

1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है धाम

सड़क मार्ग से लगभग 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर की लंबाई लगभग 65 फीट, चौड़ाई 30 फीट तथा गर्भगृह 16 फीट का बनाया गया है, मंदिर परिसर को इस प्रकार विकसित किया गया है कि एक समय में लगभग 500 श्रद्धालु दर्शन कर सकें। हाल ही में राज्य शासन ने इस क्षेत्र को धार्मिक एवं इको-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पहुंच मार्ग एवं अन्य सुविधाओं हेतु 74 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति भी प्रदान की है।

1905 से जुड़ा है सिद्धबाबा धाम का इतिहास- स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सिद्धबाबा धाम का इतिहास वर्ष 1905 से जुड़ा हुआ है, प्रारंभ में यहां एक छोटी गुफा और धूनी थी, जहां नागा साधु एवं अघोरी साधना किया करते थे, यहां स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू एवं जागृत माना जाता है, श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सिद्धबाबा के आशीर्वाद के बिना इस धाम तक पहुंचना संभव नहीं होता और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है।

एक नजर में सिद्धबाबा धाम

- केदारनाथ धाम की तर्ज पर निर्मित शिव मंदिर।
- लगभग 6 वर्षों में पूर्ण हुआ निर्माण कार्य।
- करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से हुआ निर्माण।
- 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर।
- एक साथ लगभग 500 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था।
- ओडिशा के शिल्पकारों ने की पत्थरों की नक्काशी।
- हर वर्ष मकर संक्रांति पर विशाल धार्मिक मेला आयोजित होता है।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने 74 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

मंदिर निर्माण के साथ जुड़ी जिला बनने की चर्चा- स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा का विषय है कि फरवरी 2020 में मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही मनेंद्रगढ़ को नए जिले का दर्जा मिला, हालांकि यह स्थानीय आस्था एवं जनमान्यता का विषय है,जिसे श्रद्धालु सिद्धबाबा का आशीर्वाद मानते हैं।

हर वर्ष मकर संक्रांति पर लगता है विशाल मेला- सिद्धबाबा धाम में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, प्राण-प्रतिष्ठा के बाद इस धाम के धार्मिक पर्यटन के रूप में और अधिक विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सामाजिक सौहार्द की भी दिखी मिसाल- प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व मनेंद्रगढ़ नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा का विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शोभायात्रा का स्वागत किए जाने को सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा गया।

12 जुलाई को चिरमिरी में होगा संभाग स्तरीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन

वरिष्ठ खिलाड़ी बी. मनियम की पहल,सुशिमा वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से होगा आयोजन

-संवाददाता-

चिरमिरी,27 जून 2026 (घटती-घटना)। कोयलांचल नगरी चिरमिरी में एक बार फिर शतरंज की गतिविधियों को नई गति देने की पहल की गई है। वरिष्ठ शतरंज खिलाड़ी बी. मनियम (बिच्छू भैया) के नेतृत्व तथा सुशिमा वेलफेयर फाउंडेशन, अंबिकापुर के विशेष सहयोग से चिरमिरी शतरंज क्लब द्वारा 12 जुलाई (रविवार) को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्दीबाड़ी में संभाग स्तरीय रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी होंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष

प्रतियोगिता की आयोजन समिति का नेतृत्व चिरमिरी के पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी कर रहे हैं,समिति में एसईसीएल क्षेत्रीय अस्पताल के सीएमओ डॉ. अशोक कुमार विराजी, वरिष्ठ खिलाड़ी अशोक सिंह (झगराखांड), जीवन लाल, सुभाष कश्यप, अमित विश्वास, देव प्रसाद गांगुली (देव), पूर्व सभापति श्रीमती गायत्री बिरहा, डॉ. सुमित, डीएवी स्कूल की खेल अधिकारी श्रीमती सीमा सिंह, युवा नेता राणा दास तथा आशुतोष मिश्रा को शामिल किया गया है।

तीन माह पहले हुई बैठक का परिणाम है प्रतियोगिता

लगभग तीन माह पूर्व चिरमिरी के होटल मातृछाया में खेल प्रेमियों और वरिष्ठ खिलाड़ियों की बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया था, उसी निर्णय के तहत अब 12 जुलाई को ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे क्षेत्र में शतरंज गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके।

अलग-अलग आयु वर्गों में होगी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में बालक,बालिका,महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग वर्ग बनाए गए हैं, आयु वर्ग में 9 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 14 से 15 वर्ष, 16 से 18 वर्ष तथा 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए ओपन ग्रुप रखा गया है, ताकि सभी खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके।

20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि

आयोजन समिति के अध्यक्ष के. डोमरू रेड्डी ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 20 हजार रुपये की नगद पुरस्कार राशि रखी गई है,विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे,इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मेडल एवं सहभागिता प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे।

10 जुलाई तक होगा पंजीयन

प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 जुलाई शाम 5 बजे निर्धारित की गई है, स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपये तथा अन्य प्रतिभागियों के लिए 300 रुपये रखा गया है,पंजीयन के लिए खिलाड़ी बी. मनियम (83197 96028),जीवन लाल (94242 54212) एवं के. डोमरू रेड्डी (97708 59555) से संपर्क कर सकते हैं।

छह जिलों के खिलाड़ी ले सकेंगे भाग

प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर,सरगुजा,बलरामपुर एवं जशपुर जिले के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे,प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी और शतरंज के अनुभवी आर्बिटरों की देखरेख में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 6 से 7 राउंड में संपन्न कराई जाएगी।

शतरंज संस्कृति को मिलेगा नया मंच

आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों एवं अभिभावकों से प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है,समिति का मानना है कि इस आयोजन से चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों में शतरंज जैसी बौद्धिक खेल गतिविधियों को नया मंच मिलेगा तथा युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा।

मोहर्रम की सामूहिक तस्वीर पर उठे सवाल, पुलिस अधिकारियों के साथ विवादित छवि वाले पार्षद पति की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय

शांतिपूर्ण आयोजन के बाद वायरल हुई तस्वीर...सोशल मीडिया पर प्रोटोकॉल और संदेश को लेकर बहस तेज

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,27 जून 2026 (घटती-घटना)। मोहर्रम का पर्व जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक समन्वय के लिए पुलिस प्रशासन तथा मुस्लिम समाज की सराहना भी हुई,लेकिन आयोजन के बाद सामने आई एक सामूहिक तस्वीर अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है,तस्वीर में पुलिस अधिकारियों और समाज के लोगों के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी पुलिस अधिकारियों के ठीक बगल में खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे स्थानीय स्तर पर पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पति बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति का नाम पूर्व में जुआ से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

समाज के लोग नीचे बैठे,संबंधित व्यक्ति पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ा

वायरल तस्वीर में मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग नीचे बैठकर फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं,जबकि लाल घेरे में चिन्हित संबंधित व्यक्ति पुलिस अधिकारियों के बिल्कुल समीप खड़ा नजर आ रहा है,यही दृश्य लोगों के बीच चर्चा का मुख्य कारण बना हुआ है,कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह की तस्वीरें प्रशासन की निष्पक्ष छवि को लेकर अनावश्यक सवाल खड़े कर सकती हैं।

सोशल मीडिया पर उठ रहे कई सवाल

तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं,लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति की छवि पहले से विवादों में रही हो,तो क्या उसे पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह प्रमुख स्थान पर दिखाई देना उचित संदेश देता है? वहीं कुछ लोग इसे केवल सामूहिक फोटो का संयोग मान रहे हैं और कह रहे हैं कि फोटो में किसी के खड़े होने या बैठने मात्र से किसी प्रकार के संबंध या संरक्षण का निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

पुलिस की ओर से नहीं आया कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण

अब तक इस तस्वीर को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है,यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को किसी प्रोटोकॉल के तहत अधिकारियों के साथ खड़ा किया गया था या फोटो खिंचवाने के दौरान वह स्वयं उस स्थान पर आकर खड़ा हो गया। ऐसे में तस्वीर को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

सवाल केवल तस्वीर का नहीं, सार्वजनिक संदेश का भी-

लोक जीवन में सक्रिय जनप्रतिनिधियों,सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों की सार्वजनिक उपस्थिति हमेशा लोगों के बीच संदेश छोड़ती है, ऐसे में यह तस्वीर चर्चा का विषय इसलिए बनी है क्योंकि अधिकांश समाजजन नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं,जबकि विवादित छवि वाले बताए जा रहे व्यक्ति की मौजूदगी पुलिस अधिकारियों के ठीक बगल में दिखाई दे रही है, अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या प्रशासन इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण देता है या इसे सामान्य सामूहिक तस्वीर मानकर अनदेखा किया जाएगा।

दूसरी लड़की के साथ पार्टी करते दिखे कृति सेनन के रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड कबीर बहिया,फैंस बोले...उसे पता है...?

कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह किसी और लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या कृति और कबीर का ब्रेकअप हो गया है। काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा है कि कृति सेनन बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। दोनों ने ऑफिशियल तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोला है लेकिन अक्सर इन्हें साथ में स्पॉट किया जाता है।

कृति सेनन के बर्थडे के मौके पर साथ में दोनों वेकेशन पर थे। इसके अलावा कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर की शादी में भी कबीर और कृति साथ दिखाई दिए। हालांकि अब हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं।

कृति सेनन का हुआ ब्रेकअप?

रेडिट पर हाल ही में वायरल हो रही तस्वीरों में कबीर किसी और लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या कबीर ने कृति सेनन के साथ ब्रेकअप कर लिया है?

हालांकि ये तस्वीरें रेडिउ पर शेयर की गई पोस्ट की हैं जिसका असल में एक रील से स्क्रीनशॉट लिया गया है। यह रील आलिया मोहन नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कबीर अपने दोस्तों के साथ एक शादी की पार्टी में शामिल हुए थे। कई यूजर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा- क्या कृति को इसके बारे में पता है? दूसरे ने कमेंट किया- मुझे कभी भी इससे अच्छी वाइब नहीं आई। तीसरे ने कमेंट किया - हो सकता है वो कैसेनोवा हों?

हालांकि कबीर के एक करीबी सूत्र ने बताया, ऑनलाइन वायरल हो रही कबीर और एक लड़की की तस्वीर का गलत मतलब निकाला गया है। वह उनके परिवार की दोस्त हैं और कबीर उन्हें अपनी बहन मानते हैं। यह दुखद है कि लोग कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और गलत बातें फैलाने लगते हैं।

दोनों की उम्र में 9 साल का अंतर

बता दें कि कृति और कबीर की डेटिंग की खबरों के बाद से ही इनके बीच उम्र के अंतर को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। कबीर कृति से 9 साल छोटे हैं।

जिस सांग पर जताई नाराजगी,वही बना सुपरहिट

बॉलीवुड में कई ऐसे गाने हैं जो अपनी धुन, संगीत और खास अंदाज की वजह से सालों बाद भी लोगों की यादों में बने रहते हैं। कुछ गाने अपनी कहानी और फिल्म से ज्यादा अपने संगीत और डांस की वजह से लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'चाइना गेट' का सुपरहिट डांस नंबर 'छम्मा छम्मा'। यह गाना आज भी शादियों, पार्टियों और डांस कार्यक्रमों में खूब बजाया जाता है। अपनी दमदार बीट, शानदार कोरियोग्राफी और उर्मिला मातोंडकर के जबरदस्त डांस की वजह से यह गाना बॉलीवुड के यादगार आइटम सॉन्स में शामिल हो गया।

छम्मा छम्मा' की खास बात यह है कि इसका संगीत राजस्थानी लोक संगीत से प्रेरित बताया जाता है। भारतीय लोकधुनों को बॉलीवुड में नए अंदाज में पेश करने की परंपरा पुरानी रही है और इस गाने ने भी लोक संगीत की खूबसूरती को बड़े पर्दे तक पहुंचाया। फिल्म 'चाइना गेट' में इस गाने को उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया था। भारी ज्वेलरी और पारंपरिक लुक में उर्मिला ने अपने डांस से दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। गाने की ऊर्जा और उनकी परफॉर्मेंस ने इसे उस दौर का बड़ा हिट बना दिया।

इस गाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प बताई जाती है। संगीतकार अनु मलिक और गीतकार समीर अंजान की जोड़ी ने इस गाने को तैयार किया था। कहा जाता है कि जब समीर अंजान ने पहली बार इसकी धुन सुनी तो उनका शुरुआती रिएक्शन कुछ खास सकारात्मक नहीं था। उन्हें लगा कि यह गाना शायद उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन बाद में यही गाना जबरदस्त सफलता हासिल कर गया। अनु मलिक के संगीत और समीर अंजान के बोलों ने मिलकर इस गाने को ऐसा रूप दिया कि यह दर्शकों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गया। गाने की बीट, लोक संगीत का तड़का और उर्मिला की परफॉर्मेंस ने इसे अलग पहचान दी। 'छम्मा छम्मा' सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं रहा, बल्कि यह 90 के दशक के बॉलीवुड संगीत की पहचान बन गया। आज भी जब यह गाना बजता है तो लोग इसके साथ डांस करने से खुद को रोक नहीं पाते।

गोल्डन और व्हाइट फोटोशूट में अमीई मिसोबाह का शानदार अंदाज़

अभिनेत्री अमीई मिसोबाह एक बार फिर अपने लेटेस्ट फैशन फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं। गोल्डन और व्हाइट रंग के बेहद खूबसूरत परिधान में नजर आईं अमीई ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और शालीनता से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस फोटोशूट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह तेजी से उभरती हुई फैशन आइकन हैं। तस्वीरों में अमीई विभिन्न आकर्षक पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं,जहां उनका ग्लैमर और एलिगेंस का अनोखा संगम देखने को मिलता है। गोल्डन रंग की चमक उनके लुक में लग्ज़री का एहसास जोड़ती है,वहीं व्हाइट आउटफिट उनकी सादगी और आकर्षण को और निखारता है। दोनों रंगों का यह मेल उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बेहतरीन ढंग से उभारता है। उनका बेदाग मेकअप, मनमोहक एक्सप्रेशन्स और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व पूरे फोटोशूट को एक हाई-फैशन मैगज़ीन के कवर जैसा शानदार बना देता है। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनके फैशन सेंस व स्टाइलिश अंदाज़ की जमकर सराहना कर रहे हैं।

चाहे आउटफिट की बारीकियां हों या उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने का अंदाज़, अमीई यह साबित करती हैं कि असली स्टाइल आत्मविश्वास और मौलिकता में बसता है। यह फोटोशूट न केवल उनके फैशन-फॉरवर्ड व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि हर माहौल में चमकने की उनकी क्षमता को भी उजागर करता है।

फैशन और आत्म-अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हुए अमीई ने कहा कि फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, यह आपकी पहचान का प्रतिबिंब है। जब आप अपने पहनावे में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो आपकी आंतरिक सुंदरता अपने आप निखरकर सामने आती है।

इस मनमोहक गोल्डन और व्हाइट फोटोशूट के साथ अमीई मिसोबाह ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती, आकर्षण और स्टार पावर से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फैंस इन शानदार तस्वीरों की जमकर सराहना कर रहे हैं और यह साफ है कि अमीई का फैशन सफर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

बॉलीवुड की धुनों को खास बनाने वाले व्हाईसटल किंग का सफर

बॉलीवुड फिल्मों में संगीत सिर्फ धुनों तक सीमित नहीं होता, बल्कि छोटे-छोटे साउंड इफेक्ट्स भी गानों को यादगार बना देते हैं। कभी ऑर्केस्ट्रा की शानदार धुनें,कभी पियानो की मधुर आवाज और कभी किसी कलाकार की सीटी की अनोखी धुन गाने के एहसास को और खास बना देती है। ऐसी ही एक पहचान बनाने वाले कलाकार हैं नागेश सुर्वे, जिन्हें बॉलीवुड का 'व्हाईसटल किंग' कहा जाता है। सिनेमा प्रेमियों ने कई सुपरहिट गानों में सीटी की मधुर आवाज जरूर सुनी होगी, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि इन यादगार धुनों के पीछे एक खास कलाकार का हुनर छिपा है। नागेश सुर्वे ने बॉलीवुड के कई चर्चित गानों में अपनी सीटी की आवाज से अलग पहचान बनाई है। नागेश सुर्वे ने करीब 1600 से ज्यादा गानों में सीटी बजाई है। उनकी खास शैली ने कई फिल्मों के गानों को एक अलग अंदाज दिया। उनकी सीटी की आवाज ने गानों में रोमांस,खुशी और भावनाओं को और गहरा करने का काम किया। बॉलीवुड के कई लोकप्रिय गानों में उनकी सीटी सुनाई दी है। फिल्म 'मोहब्बतें', 'फना' और 'धूम' जैसी फिल्मों के गानों में उनकी कला ने संगीत को और आकर्षक बनाया। खासतौर पर 'फना' के लोकप्रिय गाने 'चांद सिफारिश' में सीटी की धुन ने गाने की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। नागेश सुर्वे का सफर भी आसान नहीं रहा। जहां कई कलाकार अपनी आवाज या वाद्य यंत्रों से पहचान बनाते हैं, वहीं उन्होंने अपनी सीटी को ही अपनी कला का माध्यम बनाया। उन्होंने साबित किया कि संगीत में हर छोटी आवाज की अपनी अहमियत होती है। बॉलीवुड में बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इफेक्ट्स अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं, लेकिन यही चीजें किसी गाने या सीन को यादगार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। नागेश सुर्वे जैसे कलाकारों का योगदान इसी वजह से खास माना जाता है। उनकी सीटी की आवाज ने कई गानों में ऐसा जादू पैदा किया कि लोग आज भी उन धुनों को सुनकर फिल्मों के खास पलों को याद करते हैं। बिना कोई शब्द बोले सिर्फ सीटी के जरिए भावनाएं पहुंचाना उनकी कला की सबसे बड़ी खासियत है।

गोविंदा एण्ड जेठालाल की मुलाकात का दिलचस्प किस्सा

लोकप्रिय टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनकी अदाकारी ने न सिर्फ आम दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को भी उनका मुरीद बना दिया है। हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था, जिसे लेकर फैंस के बीच फिर से चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय की है जब वे टीवी शो 'क्या बात है' में काम कर रहे थे।

दिलीप जोशी के अनुसार, वे उस समय एक साउथ इंडियन किरदार निभा रहे थे और शूटिंग कमालिस्तान स्टूडियो में चल रही थी। शूट खत्म होने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि गोविंदा मेकअप रूम से बाहर निकल रहे थे और किसी अन्य शूट के लिए जा रहे थे। गोविंदा को देखते ही दिलीप जोशी खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उनसे मिलने पहुंच गए। वे यह सोचकर गए थे कि वह केवल उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वे गोविंदा के अभिनय के बड़े प्रशंसक थे।

लेकिन जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, गोविंदा ने उन्हें पहचान लिया। दिलीप जोशी के मुताबिक, यह उनके लिए बेहद हैरानी भरा पल था। गोविंदा ने उन्हें पहचानने के बाद न सिर्फ गर्मजोशी से बात की, बल्कि उन्हें गले भी लगा लिया।इस मुलाकात ने दिलीप जोशी को बेहद भावुक कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह उनके करियर के सबसे यादगार पलों में से एक है, जिसे वे आज भी नहीं भूलते। दिलीप जोशी ने कहा था कि बड़े कलाकारों से इस तरह का अपनापन मिलना किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा बन जाता है। वहीं गोविंदा अपने सहज व्यवहार और सरल स्वभाव के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, और यह किस्सा उसी की एक झलक है। फैंस के बीच यह कहानी इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि यह दिखाती है कि बड़े कलाकारों के बीच भी आपसी सम्मान और अपनापन कितना मजबूत होता है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई पल होते हैं जो पर्दे के पीछे की असली दुनिया को दर्शाते हैं।कुल मिलाकर, यह किस्सा न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि यह भी बताता है कि प्रतिभा और सम्मान किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होते।

डॉन 3 विवाद पर आया बड़ा बयान

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 से अभिनेता रणवीर सिंह के कथित रूप से बाहर होने और उसके बाद मेकर्स के साथ उपजे विवाद ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले पर अब फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी का एक बेहद बड़ा और बेबाक बयान सामने आया है। सुनील शेट्टी ने खुलकर रणवीर सिंह का समर्थन किया है और किसी भी कलाकार को बैन या ब्लैकलिस्ट करने की मानसिकता पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस अभिनेता ने अपने दम पर फिल्म उद्योग को हजारों करोड़ रुपये का बिजनेस दिया है, उसे काम करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब सुनील शेट्टी अपनी आगामी मल्टीस्टारर फिल्म %वेलकम टू द जंगल के प्रचार के सिलसिले में मीडिया से मुखातिब थे। एक विशेष बातचीत के दौरान जब उनसे रणवीर सिंह और डॉन 3 के निर्माताओं के बीच चल रहे विवाद और उन पर बैन लगाने की मांग को लेकर सवाल पूछा गया, तो वे भड़क गए। सुनील शेट्टी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी अभिनेता को काम करने से नहीं रोक सकता।

खेल समाचार

महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए भारत समेत 9 टीमों ने किया क्वालीफाई

पाकिस्तान का महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है...लेकिन इसके बावजूद उन्हें खास वजह के चलते अगले संस्करण के लिए जगह मिल गई है...

नई दिल्ली,27 जून 2026। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की धूम के बीच अगले संस्करण को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। बीते शुक्रवार यानि 26 जून को श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले के बाद उन 9 टीमों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने साल 2028 में होने वाले टूर्नामेंट में सीधे एंट्री कर ली है। इसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। बता दें कि पाक टीम को मेजबान होने की वजह से महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे जगह मिली है।

पाकिस्तान को मिला मेजबान होने का फायदा

पाकिस्तान का महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 4 मैच खेलने के बावजूद उनके खाते में एक भी जीत नहीं आई है। महिला टी20 वर्ल्डकप 2026 में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। जिन्हें 6-6 के ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रूप की टॉप-4 टीमों के लिए अगले संस्करण के दरवाजे खुलने हैं। पाकिस्तान फिलहाल अपने ग्रूप में 5वें स्थान की टीम है। लेकिन मेजबान होने के चलते उनकी सीट पक्की है।

इन 8 टीमों को मिली जगह

ग्रूप-ए में से भारत,ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, और दक्षिण अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन के आधार पर अपनी जगह बनाई है। जबकि ग्रूप-बी से इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका टॉप-4 में पहुंची हैं। 10वीं टीम का फैसला 6 जुलाई तक आईसीसी की रैंकिंग का आधार पर किया जाएगा। आयरलैंड फिलहाल इस रेस में सबसे आगे मानी जा सकती है। 201 रेटिंग पॉइंट्स के साथ यह टीम 9वें पायदान पर काबिज है।

स्कॉटलैंड ने गंवाया मौका

श्रीलंका को मात देकर स्कॉटलैंड के पास महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे क्वालीफाई करने का सुनहरा मौका था। जिसको उन्होंने अपनी गलती से गंवा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 152 रन का लक्ष्य दिया था। जिसका पीछा करते हुए लंकाई टीम ने 118 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इस मौके पर स्कॉटलैंड की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन फिर आखिरी 3 ओवर में खेल का पासा पलटा। श्रीलंका ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद और 3 विकेट शेष रहते जीत अपने नाम कर ली।

पराग्वे-ऑस्ट्रेलिया के बीच ड्रॉ रहा मैच,तुर्की ने अमेरिका को हराया

नई दिल्ली,27 जून 2026। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-डी में पराग्वे फुटबॉल टीम और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। लेवाइस स्टेडियम में हुए मैच में कोई गोल देखने को नहीं मिला। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में तुर्की ने अमेरिका फुटबॉल टीम को 3-2 से शिकस्त दी। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने राउंड ऑफ-32 के लिए प्रवेश किया, जबकि तुर्की का सफर समाप्त हो गया।लगभग 65 हजार दर्शकों की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाफ में बेहतर शुरूआत की और कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने उन प्रयासों को नाकाम किया। दूसरे हाफ में पराग्वे ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन कोई निर्णायक मौका नहीं बना पाई। मैच में ड्रॉ के साथ ऑस्ट्रेलिया संतुष्ट दिखी क्योंकि इस परिणाम से उन्होंने नॉकआउट में पहुंचने में सफलता हासिल की।फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार नॉकआउट में पहुंचने में कामयाब रही। इससे पहले 2006 और 2022 में राउंड ऑफ-16 में पहुंचने में सफल रही थी। इन 2 संस्करणों में कुल 32-32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 48 टीमें शामिल रही। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्टन ट्रस्टी ने तीसरे ही मिनट में गोल करके बढ़त दिला दी। कुछ समय बाद ही 10वें मिनट में अर्दा गुलेर ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। वहीं, अल्पर यिलमाज ने पहले हाफ में गोल करके तुर्की को बढ़त में ला दिया। इसके बाद अमेरिका के सेबेस्टियन बरहाल्टर ने 49वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। कान आयहान ने अंतिम क्षणों (90+8′) में गोल दागकर तुर्की को जीत दिलाई।मैच में अमेरिका ने गोल करने की 19 बार कोशिश की और 7 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ तुर्की ने 10 बार ही कोशिश की और 4 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में अमेरिकी टीम के पास 53 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। अमेरिका ने 87 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 489 पास पूरे किए। तुर्की ने 412 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 81 प्रतिशत की रही।

मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर

नौगई पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा

नौगई हत्याकांड: मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा, स्वास्थ्य मंत्री ने कराई सीधी बातचीत

नौगई पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री,मुख्यमंत्री से कराई पीड़ित परिवार की बात

बोले-दोषियों को मिलेगी कठोरतम सजा

नौगई हत्याकांड पर सरकार गंभीर...मुख्यमंत्री से फोन पर हुई पीड़ित परिवार की बात...

मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से की मुलाकात,मुख्यमंत्री से फोन पर कराई सीधी बातचीत,दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई का दिया भरोसा...

रवि सिंह

कोरिया,27 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16 और 17 जून की दरमियानी रात हुए जघन्य तिहरे हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाईं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बैकुंठपुर पहुंचे और वहां से नौगई गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की,उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इस अमानवीय घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं और कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पहले श्रद्धांजलि,फिर परिजनों से लंबी चर्चा

स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले जघन्य वारदात में जान गंवाने वाले तीनों मृतकों के छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, इसके बाद उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और उनकी पीड़ा को सुना,मंत्री ने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे,नौगई हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच लोगों पर सुनियोजित हमला किया गया था, इस हमले में तीन लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई,जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए,इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

मुख्यमंत्री से कराई सीधी बातचीत

मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री से सीधे फोन पर बातचीत कराई,मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है,उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराध की भयावहता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि न्याय दिलाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सरकार स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रही है।

मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है,प्रदेश में जब मुख्यमंत्री किसी कारणवश स्वयं किसी घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते, तब वे अपने प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ मंत्री को भेजते हैं,नौगई में स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री का सीधे पीड़ित परिवार से संवाद यह संकेत देता है कि राज्य सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है,मंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार केवल सांत्वना देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।

सरकार के बड़े फैसले की चर्चा

मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि सरकार आगे जांच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है,लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से लगातार संवाद स्थापित किया गया है,उससे यह माना जा रहा है कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही या जांच में कमी नहीं चाहती,विशेषज्ञों का मानना है कि इतने संवेदनशील मामले में यदि आवश्यकता हुई तो जांच की निगरानी और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए जा सकते हैं, हालांकि यह संभावनाओं और चर्चाओं का विषय है,जिसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

परिजनों में जगा भरोसा

मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार में कुछ हद तक भरोसा दिखाई दिया,परिजनों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी पीड़ा को समझते हुए दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी,जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो,क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि सरकार द्वारा तत्काल प्रतिनिधि भेजना और मुख्यमंत्री का स्वयं पीड़ित परिवार से संवाद करना यह दर्शाता है कि नौगई हत्याकांड को केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर मानवीय और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले के रूप में देखा जा रहा है,अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और सरकार अपने आश्वासनों को किस प्रकार धरातल पर उतारती है। पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा मिले और उन्हें न्याय प्राप्त हो।

पुराने पेंशनर्स के लिए हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी..मिलेगा 59 महीने का बकाया एरियर,राज्य सरकार की अपील खारिज

बिलासपुर,27 जून 2026। छत्तीसगढ़ के हजारों पेंशनर्स को राहत देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर किसी प्रकार की सहमति या विवाद का असर पेंशनभोगियों के वैध अधिकारों पर नहीं पड़ सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा एरियर भुगतान के दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत लंबित 59 माह के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। यह मामला छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय पुराने पेंशनर्स के साथ भेदभाव किया। छठवें वेतन आयोग के लाभ के लिए 1 सितंबर 2008 और सातवें वेतन आयोग के लिए 1 अप्रैल 2018 की कट-ऑफ तिथि तय कर दी गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में पेंशनर्स को क्रमशः 32 माह और 27 माह के एरियर से वंचित होना पड़ा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दिया यह तर्क

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के तहत वित्तीय हिस्सेदारी के संबंध में मध्य प्रदेश की सहमति आवश्यक है। हालांकि पेंशनर्स की ओर से इस दलील का विरोध किया गया और बताया गया कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एरियर भुगतान के लिए ऐसी सहमति जरूरी नहीं है।

वक्फ संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार...कहा...ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई का अधिकार,2 महीने में फैसला करने के निर्देश

बिलासपुर,27 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उन पर कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादों की सुनवाई और समाधान का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब वक्फ अधिनियम के तहत विवाद सुलझाने का कानूनी प्रावधान मौजूद है, तो सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके. प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता मोहम्मद अजमल खान ने कवर्धा की जामा मस्जिद मुस्लिम ट्रस्ट की वक्फ संपत्ति पर मुतवल्ली (प्रबंधक) की ओर से कथित अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सीईओ के आदेश के भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

याचिका में कहा गया कि वक्फ बोर्ड के सीईओ की ओर से कथित निर्माण रोकने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही वक्फ अधिनियम की धारा 8) के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन पेश किया था, लेकिन ट्रिब्यूनल में कोरम नहीं होने के कारण सुनवाई पेंडिंग थी।

छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद-विधायक पर आपराधिक केस

इनमें भूपेश बघेल-देवेंद्र यादव और मधुसूदन यादव के नाम,हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट जारी...

बिलासपुर,27 जून 2026। छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामले पेंडिंग हैं। हाईकोर्ट की ओर से जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक केसों में सुनवाई चल रही है। जारी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,वर्तमान विधायक कवासी लखमा,देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व, वर्तमान विधायकों के मामलों की नियमित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग और सुनवाई हो रही है। रायपुर की विशेष कोर्ट में इस वक्त सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। रायपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक मामला क्रमांक 5465/2018 दर्ज है। इन नेताओं पर आईपीसी की धारा 120बी,469,471 और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसकी सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख तय की गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई

इसके अलावा रायपुर की ही प्रथम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में वर्तमान विधायक कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी के विशेष मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसमें अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होनी है। साथ ही ईडी की ओर से विधायक कवासी लखमा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई भी जून महीने में ही तय की गई थी।

धोखाधड़ी का भी मामला पेंडिंग : जांजगीर-चांपा जिले में आरोपी बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी (फ्रॉड) और मारपीट के मामले चले रहे हैं। जिला न्यायालय में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस की सुनवाई चल रही है। कवर्धा में अशोक कुमार साहू और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में 17 जून 2026 को कोर्ट में साक्ष्य (सबूत) पेश करने की तारीख तय की गई थी। गरियाबंद जिले के सीजेएम कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी के खिलाफ रास्ता रोकने और मारपीट (बलवा) के मामलों में धारा 341 और 147 के तहत 25 जून 2026 को सुनवाई तय है। वहीं रोहित साहू के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में से एक केस मई में दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, जबकि दूसरे मामले की सुनवाई भी 25 जून को ही होनी है।

भाजपा के पूर्व सांसद पर भी केस लंबित

इसके अलावा राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ निवेशकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में छह केस चल रहे हैं। इनमें से तीन मामलों की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में ही इन मामलों की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। हालांकि, इसी कोर्ट में दर्ज तीन अन्य मामलों में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वहां अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं।

कई जिलों में भी चल रहे केस

बिलासपुर के सीजेएम कोर्ट में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और बाकियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत 1 जुलाई 2026 को आरोप तय होने हैं। बलौदाबाजार की तीसरी एडीजे कोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ बलवा और हत्या के प्रयास के तहत आईपीसी की धारा 307, 435, 436, 153ए के मामले में 23 जून 2026 को सुनवाई की तारीख तय थी। बलौदाबाजार में ही पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ दर्ज सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के केस में 13 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है।

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज,बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी

रायपुर,27 जून 2026। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह कदम इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। बैठक में निदेशक मंडल ने परियोजना की अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर सभी तकनीकी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। बड़े व्यास की ड्रिलिंग से किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार का सटीक आकलन किया जाएगा। इसके

बाद विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित रही है, लेकिन बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद यह बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एनसीएल द्वारा स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग,भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किम्बरलाइट पाइप की पहचान की गई। इसके बाद लगभग 200 टन बल्क सैंपल का परीक्षण एनएमडीसी के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में किया गया, जहां 1.22 कैरेट वजन के पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए। इससे इस क्षेत्र में हीरा युक्त भू-संरचना की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख हीरा उत्पादक देशों के अनुभव बताते हैं कि प्रारंभिक चरण में इस प्रकार की सफलता भविष्य में बड़े व्यावसायिक भंडार मिलने का संकेत हो सकती है। इसलिए बलौदा-बेलमुंडी परियोजना को छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण खनिज परियोजना माना जा रहा है। बैठक में राज्य की अन्य प्रमुख लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

दुर्ग पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 10 थाना और चौकी प्रभारियों के तबादले,वैशाली नगर सुपेला,छावनी समेत कई थानों को मिले नए प्रभारी

दुर्ग-भिलाई,27 जून 2026। दुर्ग पुलिस में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने शनिवार को आदेश जारी कर जिले के 10 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से नई जगह पर भेजा गया है। अब वैशाली नगर,पद्मनाभपुर,धमधा, नंदनी,उतई,सुपेला,पुरानी भिलाई और छावनी जैसे प्रमुख थानों में नए थाना प्रभारी जिम्मेदारी संभालेंगे। जारी आदेश के मुताबिक वैशाली नगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत मिश्रा को एसीसीयू (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) दुर्ग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं एसीसीयू में पदस्थ निरीक्षक प्रमोद श्रीरिया को पद्मनाभपुर थाना प्रभारी

की जिम्मेदारी दी गई है। नियंत्रण कक्ष भिलाई में पदस्थ निरीक्षक महेश ध्रुव अब धमधा थाना की कमान संभालेंगे। उतई थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल पटेल का तबादला नंदनी थाना कर दिया गया है। वहीं पद्मनाभपुर थाना प्रभारी रहे निरीक्षक राजकुमार लहरे को वैशाली नगर थाना भेजा गया है। सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव को पुरानी भिलाई थाना प्रभारी बनाया गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)